

करेंट अफेयर्स

राजस्थान

(संग्रह)



जनवरी

2026

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान	5
● कोटा-हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026.....	5
● राजस्थान मे AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस.....	5
● राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्राप्त हुआ.....	6
● राजस्थान में माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन और एक्सपो 2026.....	7
● राजस्थान की बामनवास कांकड़ पहली पूर्ण जैविक पंचायत बनी.....	7
● जयपुर में क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन हुआ.....	8
● राजस्थान में भारतीय ऊन क्षेत्र पर चिंतन शिविर.....	8
● कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इको-सेंसिटिव जोन घोषित.....	9
● नीति आयोग ने जयपुर में सर्कुलर इकोनॉमी पर तीन रिपोर्ट लॉन्च कीं.....	10
● राजस्थान में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये वार्षिक कार्य योजनाएँ.....	10
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स	12
● पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'अंजदीप'.....	12
● भारत में पहली 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी.....	12
● प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के 25 वर्ष.....	13
● भारत में तीन नई एयरलाइंस.....	14
● कैसर उपचार अवसंरचना हेतु NTPC-GCRI समझौता ज्ञापन (MoA).....	14
● IIT मद्रास ने ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया.....	15
● कलाई-II जलविद्युत परियोजना.....	15
● उपराष्ट्रपति ने किया 'सिंग, डांस एंड लीड' पुस्तक का विमोचन.....	16
● दिल्ली सरकार ने RBI के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये.....	16
● पिपरावा के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन.....	17
● भारत में IICDEM-2026 का आयोजन.....	17
● धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया.....	18
● 'आशा वैन' मोबाइल यूनिट.....	18
● IIT मद्रास में सुपरकंप्यूटर परम शक्ति लॉन्च किया.....	19

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



● अकासा एयर IATA में पाँचवीं भारतीय सदस्य के तौर पर शामिल.....	19
● अरुणाचल प्रदेश में 1720 मेगावाट कमला जलविद्युत परियोजना	20
● अरलम तितली अभयारण्य.....	20
● वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 में MSME के लिये PFRDA NPS आउटरीच.....	21
● न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे मेघालय उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त.....	21
● 'नशा मुक्त परिसर' अभियान का उद्घाटन.....	22
● MoEFCC ने लॉन्च किया संस्थागत समन्वय हेतु 'NIRANTAR' प्लेटफॉर्म.....	23
● विशाखापत्तनम में भारतीय प्रकाशस्तंभ महोत्सव का उद्घाटन.....	23
● नमामि गंगे के तहत जलीय जैव विविधता पहल शुरू की.....	24
● गुजरात में हाई-रिस्क पैथोजेन हेतु भारत की पहली राज्य-वित्तपोषित BSL-4 लैब	24
● विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी की.....	25
● गुजरात ने 'पोषण उड़ान 2026' शुरू किया	26
● तमिलनाडु में बनेगा भारत का पहला 'साँवरेन AI पार्क'.....	27
● इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के तौर पर पहला ONDC ऑर्डर डिलीवर किया.....	27
● IOA ने नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया	28
● निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में केरल देश में अग्रणी	28
● होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी	29
● हैदराबाद में जनजातीय चिकित्सकों के लिये राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम	29
● MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में टेक्नोलॉजी सेंटर को स्वीकृति दी	30
● त्रिपुरा में 48वाँ कोकबोरोक दिवस समारोह.....	31
● IIT दिल्ली में पावर सेक्टर रेगुलेशन के लिये CoE.....	31
● महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट से एक दुर्लभ सीसिलियन की खोज.....	32
● C-DOT को सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिये SKOCH अवार्ड 2025 मिला	33
● खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 लद्दाख में.....	33
● नई दिल्ली में द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन.....	34
● स्ट्राइप टाइगर चंडीगढ़ की राजकीय तितली घोषित	35
● केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राष्ट्रीय वन प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की.....	35
● DGCA ने ATPL के लिये इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस सर्विस शुरू की	36
● अमेलिया वाल्वरडे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का हेड कोच नियुक्त किया.....	37
● महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये भारत की पहली टेलिंग्स नीति.....	37
● टाटा ग्रुप बना भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड; एप्पल पूरे विश्व में अग्रणी.....	38
● NHAI और कोंकण रेलवे ने इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिये MoU पर हस्ताक्षर किये.....	39
● ICAR और BISA ने ACASA-इंडिया लॉन्च किया तथा NICRA के 15 वर्ष की समीक्षा की	39

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



● इंडिया एनर्जी वीक 2026.....	40
● गुजरात में स्थापित भारत की पहली निजी उपग्रह निर्माण सुविधा.....	41
● ह्यूमनॉइड रोबोट 'ASC अर्जुन'.....	41
● सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026	42
● WEF आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करेगा	43
● त्रिपुरा में माताबारी पर्यटन सर्किट परियोजना	43
● बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड ICC पुरुष T20 विश्व कप में शामिल.....	44
● सर्वानंद सोनोवाल ने विडिंजम बंदरगाह क्षमता विस्तार कार्यों का उद्घाटन किया	44
● CSIR-CRRI और JSW स्टील ने तमिलनाडु में स्टील स्लैग सड़कें बनाने के लिये साझेदारी की	45
● राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 में 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिये.....	46
● DRI द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन सहाय्यी चेकमेट.....	47
● विंग्स इंडिया 2026	47
● तेलंगाना पुलिस ने घर बैठे FIR दर्ज कराने की सुविधा शुरू की.....	48
● शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र 2026 से सम्मानित	48
● अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लॉन्च किया पहला आधार-इंटीग्रेटेड PATHIK सिस्टम	49
● नोवाक जोकोविच ने 400वीं ग्रैंड स्लैम मैच जीत हासिल की.....	50
● माइक्रोसॉफ्ट ने माईया 200 AI चिप्स लॉन्च किये.....	50
● राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार 2025-26	51
● केरल में PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया	51
● गूगल डीपमाइंड का अल्फाजीनोम AI टूल.....	52
● महाराष्ट्र की झॉकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहला स्थान जीता.....	53
● PFRDA ने किया NPS के लिये SAARG पर विशेषज्ञ समिति का गठन.....	53
● केरल आधिकारिक तौर पर 'राज्य सूक्ष्मजीव' घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना.....	54

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान

कोटा-हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026

चर्चा में क्यों ?

हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चंबल नदी तट पर प्रथम कोटा-हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु

- आयोजक: इस कार्यक्रम का आयोजन होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान (HFR) द्वारा राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से तथा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के समर्थन से किया गया।
- उद्घाटन: इस ट्रेवल मार्ट का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया।
- उद्देश्य: इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य हाड़ौती क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग के विभिन्न हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसके अंतर्गत क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबल नदी आधारित पर्यटन अनुभव, ऐतिहासिक किले तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया।
- हाड़ौती का विस्तार: यह मार्ट हाड़ौती क्षेत्र के चार जिलों- कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां पर केंद्रित है।
- पर्यटन को बढ़ावा: इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय पर्यटन को समग्र पहचान दिलाने का प्रयास किया गया। साथ ही, इस आयोजन के दौरान राजस्थान पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, जिससे हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन संवर्द्धन के प्रयासों को और सुदृढ़ता मिली।

राजस्थान में AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस

चर्चा में क्यों ?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने घोषणा की है कि राजस्थान जनवरी 2026 में जयपुर में क्षेत्रीय 'AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस' की मेज़बानी करेगा।

मुख्य बिंदु

- पूर्व-आयोजित पहल: यह आयोजन इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिये एक पूर्व-तैयारी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य AI के अंगीकरण और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य शासन सुधार, आर्थिक वृद्धि, नवाचार तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका का अन्वेषण करना है।
- मुख्य एजेंडा: विमर्श का आधार "तीन सूत्र" (People, Planet, Progress) तथा IndiaAI मिशन के "सात चक्र" हैं।
- प्रमुख क्षेत्र: इस आयोजन में सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये AI, नैतिक AI व्यवहार तथा शहरी नियोजन और प्रशासन में डिजिटल ट्विन्स जैसे अनुप्रयोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ महत्त्व: यह पहल सतत विकास के लिये AI के उपयोग, शासन दक्षता में सुधार तथा राजस्थान जैसे राज्यों को AI नवाचार के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

परिचय:

- AI का आशय कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के ऐसे कार्य करने की क्षमता से है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किये जाते हैं क्योंकि ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है।
- हालाँकि अभी ऐसी कोई AI प्रणाली नहीं है जो एक सामान्य मानव द्वारा किये जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सके, हालाँकि कुछ AI मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम हो सकते हैं।

विशेषताएँ और घटक:

- डीप लर्निंग (DL) तकनीक बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा जैसे- टेक्स्ट, चित्र या वीडियो के माध्यम से ऑटोमेटिक लर्निंग को सक्षम बनाती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आदर्श विशेषता इसकी युक्तिसंगत कार्रवाई करने की क्षमता है जिसमें एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। **मशीन लर्निंग (ML)**, AI का ही एक प्रकार है।

राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्राप्त हुआ

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने राजस्थान के नागौर ज़िले में उगाए जाने वाले नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन (GI) प्रदान किया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **GI मान्यता:** मारवाड़ क्षेत्र के नागौर में उत्पन्न नागौरी अश्वगंधा को उसकी विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और भौगोलिक उत्पत्ति के लिये आधिकारिक रूप से **भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन (GI)** प्रदान किया गया है।
- ◆ **आर्थिक लाभ:** GI टैग उत्पाद के नाम को संरक्षण प्रदान करता है, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है और किसानों को आयुर्वेदिक तथा फार्मास्यूटिकल बाजारों से सीधे जुड़कर अधिक लाभकारी मूल्य हासिल करने में सहायता करता है।
- ◆ **निर्यात बढ़ावा:** GI प्रमाणन के बाद केवल प्रमाणित नागौरी अश्वगंधा ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेची जा सकेगी, जिससे निर्यात के अवसर बढ़ने और वैश्विक हर्बल एवं औषधीय बाजार में इसकी मांग बढ़ने की संभावना है।
- ◆ **भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन (GI):** भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
- ◆ **मंत्रालय:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- **विभाग:** भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, जो पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय (CGPDTM) के अंतर्गत कार्य करती है।
- ◆ **राजस्थान का GI परिदृश्य:** नागौरी अश्वगंधा को शामिल किये जाने के बाद राजस्थान के कुल GI-टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जिनमें बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल और कोटा डोरिया जैसे प्रसिद्ध उत्पाद भी शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान में माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन और एक्सपो 2026

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर, राजस्थान में आयोजित माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन और एक्सपो 2026 को संबोधित किया।

मुख्य बिंदु

- ♦ **आयोजक:** माहेश्वरी समुदाय
- ♦ **माहेश्वरी समुदाय:** माहेश्वरी समुदाय ने ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम, व्यापार, उद्योग और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।
 - ⦿ **परंपरा और आधुनिकता का संगम:** यह समुदाय निर्माण, कौशल विकास, उद्यमिता और आधुनिक तकनीक अपनाने के माध्यम से यह दिखाता है कि परंपरा तथा प्रगति एक साथ आगे बढ़ सकती हैं।
- ♦ **आत्मनिर्भरता का संदेश:** आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और भारतीय भाषाओं (स्वभाषा) के प्रोत्साहन को महत्व दिया गया।
- ♦ **सामाजिक एकता:** मजबूत एवं संगठित समुदाय राष्ट्र-निर्माण और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं।
- ♦ **भारत की वैश्विक आर्थिक प्रगति:** भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है।

राजस्थान की बामनवास कांकड़ पहली पूर्ण जैविक पंचायत बनी

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ ज़िले की बामनवास कांकड़ पंचायत राज्य ही नहीं बल्कि उत्तर-पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक-प्रमाणित पंचायत बन गई है।

मुख्य बिंदु:

- ♦ **प्रमाणीकरण:** COFED (कोफार्मिन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ एंड प्रोड्यूसर कंपनीज़) द्वारा प्रमाणन सुगम बनाया गया।
 - ⦿ COFED ने जैविक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये तकनीकी और बाज़ार सहायता प्रदान की।
 - ⦿ पंचायत को नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन (NPOP) मानकों के तहत पूर्णतः जैविक पंचायत के रूप में प्रमाणित किया गया।
- ♦ **समुदाय-आधारित पहल:** रासायनिक-मुक्त कृषि का परिवर्तन स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिला किसानों द्वारा संचालित था, जो मृदा के क्षरण, भूजल समस्याओं और रसायनों से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण प्रेरित हुआ।
- ♦ **रसायन-मुक्त कृषि की प्रतिज्ञा:** किसानों ने सिंथेटिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न करने की शपथ ली।
- ♦ **सतत विकास का मॉडल:** यह पंचायत जैविक कृषि, पशुपालन और पर्यावरण संरक्षण को जोड़कर सतत ग्रामीण विकास का एक ऐसा मॉडल निर्मित करती है जिसे अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



जयपुर में क्षेत्रीय श्रम एवं रोज़गार सम्मेलन का उद्घाटन हुआ

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के जयपुर में दो दिवसीय (14-15 जनवरी, 2026) क्षेत्रीय श्रम एवं रोज़गार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारत के चार नए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- ♦ **जयपुर सम्मेलन:** यह पूरे देश में नए श्रम नियामक ढाँचे को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये छह क्षेत्रीय परामर्श सत्रों की श्रृंखला का हिस्सा है।
- ♦ **भागीदार:** उत्तर-पश्चिमी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम और उद्योग सचिव सम्मेलन में शामिल हुए ताकि व्यवसाय करने में आसानी पर चर्चा की जा सके।
- ♦ **सम्मेलन का उद्देश्य:** मुख्य उद्देश्य चार नए श्रम संहिताओं के सुगम क्रियान्वयन, वेब-आधारित निरीक्षण प्रणाली में संक्रमण और सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करना है।
 - ⦿ ये संहिताएँ भारत के श्रम और रोज़गार नियामक ढाँचे को आधुनिक बनाने तथा सुव्यवस्थित करने के लिये तैयार की गई हैं।
- ♦ **श्रम सुधार:** 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित किया गया है ताकि अनुपालन सरल हो और श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।
- ♦ **ई-श्रम पोर्टल:** सम्मेलन में ई-श्रम पोर्टल को अन्य डेटाबेस के साथ एकीकृत करने और असंगठित श्रमिकों को बिना रुकावट लाभ उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई।
- ♦ **महत्त्व:** श्रम सुधारों में संघीय समन्वय को मज़बूत करना, नई संहिता के नियमों को त्वरित रूप से अंतिम रूप देना और विभिन्न राज्यों में श्रम प्रशासन तथा रोज़गार सेवाओं को सुधारना है।

राजस्थान में भारतीय ऊन क्षेत्र पर चिंतन शिविर

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (CWDB), वस्त्र मंत्रालय ने जनवरी 2026 में राजस्थान के अ विकानगर में भारतीय ऊन क्षेत्र पर चिंतन शिविर का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु:

- ♦ **कार्यक्रम का नाम:** भारतीय ऊन क्षेत्र की चुनौतियों, अवसरों और भविष्य की संभावनाओं पर 'चिंतन शिविर', जो ICAR-केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान (CSWRI), अ विकानगर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
- ♦ **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य भारत की आयातित उत्तम श्रेणी की ऊन पर भारी निर्भरता को कम करना था, जिसके तहत:
 - ⦿ ऊन मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना
 - ⦿ स्थायी भेड़ पालन और ऊन उत्पादन को बढ़ावा देना
 - ⦿ ऊन और तकनीकी वस्त्रों में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना
 - ⦿ भारतीय ऊन के विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देना
 - ⦿ ऊन प्रसंस्करण के लिये साझा सुविधा केंद्र (CFCs) का विस्तार करना

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य सिफारिशें:

- ऊन ब्रांडिंग और गुणवत्ता के लिये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना
- ऊन प्रसंस्करण में अवसंरचना और तकनीक को सुधारना
- किसानों, MSME और उद्योग के बीच संबंध मजबूत करना
- मूल्य संवर्द्धन और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना
- ◆ प्रदर्शनी: भेड़ की नस्लों, ऊन परिधान, तकनीकी वस्त्र, नवाचार और स्टार्ट-अप योगदान सहित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- ◆ महत्त्व: यह ग्रामीण आजीविका को सहारा देता है, भारत के ऊन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाता है और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ संरेखित है।

कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने राजस्थान स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) के रूप में अधिसूचित किया है।

मुख्य बिंदु:

- ◆ अधिसूचना जारी करने वाला प्राधिकरण: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
- ◆ स्थिति: कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित है।
 - आवृत ज़िले: उदयपुर, पाली, राजसमंद
- ◆ इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) का विस्तार: अधिसूचित ESZ अभयारण्य की सीमा से 0 से 1 किमी तक फैला है।
 - यह लगभग 243 वर्ग किमी क्षेत्र को शामिल करता है और इसमें लगभग 94 गाँव शामिल हैं।
- ◆ ESZ का उद्देश्य: संरक्षित वन क्षेत्र और आसपास की मानव बस्तियों के बीच बफर ज़ोन के रूप में कार्य करना, ताकि जैव-विविधता संरक्षण, आवास सुरक्षा तथा पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।
- ◆ प्रतिबंधित गतिविधियाँ: ESZ के भीतर वाणिज्यिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, ईट-भट्टे तथा नए बड़े पैमाने के निर्माण कार्य (रिसॉर्ट/होटल) निषिद्ध या कड़े रूप से विनियमित हैं।
 - कृषि, बागवानी, वर्षा-जल संचयन तथा पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को सख्त पर्यावरणीय मानकों के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है।
- ◆ पारिस्थितिक महत्त्व: जंगली बिल्ली, भारतीय पेंगोलिन, नीलगाय और चिंकारा जैसे वन्यजीवों का आवास है, जिससे इसका पारिस्थितिक महत्त्व अत्यधिक बढ़ जाता है।
- ◆ प्रशासनिक प्राधिकरण: यह अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी की गई है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नीति आयोग ने जयपुर में सर्कुलर इकोनॉमी पर तीन रिपोर्ट लॉन्च कीं

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग ने जनवरी 2026 में राजस्थान के जयपुर में भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को सुदृढ़ करने पर केंद्रित तीन व्यापक रिपोर्ट जारी कीं, जिनमें एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ELVs), अपशिष्ट टायर, ई-अपशिष्ट तथा लिथियम-आयन बैटरियाँ शामिल हैं।

मुख्य बिंदु:

- ❖ **कार्यक्रम:** ये रिपोर्ट राजस्थान के जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल मैटीरियल रिसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस (IMRC) 2026 के दौरान जारी की गईं।
- ❖ **आयोजक:** इसका आयोजन मैटीरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MRAI) द्वारा किया गया।
- ❖ **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी इकोसिस्टम में चुनौतियों एवं अवसरों का विश्लेषण करना तथा अवसंरचना विकास, क्षेत्रों के औपचारिकीकरण और राजस्व सृजन के लिये नीतिगत सिफारिशें करना है।
- ❖ **इन् रिपोर्टों में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR)** फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने और प्रमुख अपशिष्ट क्षेत्रों में संसाधन दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- ❖ **रणनीतिक महत्त्व:** यह 'विकसित भारत 2047' फ्रेमवर्क के अंतर्गत संसाधन-दक्ष, निम्न-कार्बन विकास की भारत की परिकल्पना के अनुरूप।
- ❖ **स्वच्छ ऊर्जा में भूमिका:** बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बिक्री के बीच लिथियम-आयन बैटरियों की बढ़ती मांग और उनके जीवन-चक्र के अंत में सतत प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मैटीरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MRAI):

स्थापना: MRAI की स्थापना 1 नवंबर, 2011 को की गई थी।

भूमिका: यह भारत में रिसाइक्लिंग उद्योग का शीर्ष निकाय है, जो सतत अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

राजस्थान में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये वार्षिक कार्य योजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले राजस्थान के जिलों द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु अपनाई गई वार्षिक कार्य योजनाओं (AAPs) और क्षेत्र-विशिष्ट उपायों की समीक्षा की।

मुख्य बिंदु:

- ❖ **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य वार्षिक कार्य योजनाओं (AAPs) के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों की तैयारी और क्रियान्वयन का आकलन करना है।
- ❖ **कानूनी स्थिति:** यह CAQM अधिनियम, 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- ❖ **CAQM के निर्देश:** क्रियान्वयन तंत्र को मजबूत करना, अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना, निवारक उपाय अपनाना तथा रियल-टाइम निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार करना।
- ❖ **लक्ष्य:** PM2.5 और PM10 के स्तर को कम करना तथा NCR राज्यों में समान वायु गुणवत्ता प्रबंधन सुनिश्चित करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- **PM10 (स्थूल कण):** 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।
- **PM2.5 (सूक्ष्म कण):** 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।
- ◆ **फोकस क्षेत्र:** परिवहन, उद्योग, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (C&D), सड़क की धूल, जैव-अपशिष्ट व अपशिष्ट दहन आदि।
- ◆ **महत्त्व:**
 - **क्षेत्रीय दृष्टिकोण:** NCR राज्यों में वायु प्रदूषण को सीमा-पार समस्या के रूप में संबोधित करता है।
 - **नीति एकीकरण:** राज्य कार्य योजनाओं को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता लक्ष्यों के अनुरूप सुनिश्चित करता है।
 - **जन-स्वास्थ्य प्रभाव:** लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने का लक्ष्य रखता है।
 - **शासन सुदृढीकरण:** जिला और राज्य स्तर पर जवाबदेही तथा क्रियान्वयन दक्षता बढ़ता है।
- ◆ **ढाँचा-सामंजस्य:** ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के साथ संरेखण।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'अंजदीप'

चर्चा में क्यों ?

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित तीसरा पनडुब्बी-रोधी शैलो वाटर युद्धपोत (ASW-SWC) 'अंजदीप' को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

मुख्य बिंदु

अंजदीप के बारे में:

- इस पोत को चेन्नई स्थित INS अड्यार में भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया गया।
- इसका डिजाइन और निर्माण स्वदेशी रूप से गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा एल एंड टी शिपयार्ड, कट्टुपल्ली के सहयोग से किया गया है।

तकनीकी क्षमताएँ:

- यह युद्धपोत हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी पनडुब्बी-रोधी रॉकेट प्रणाली तथा शैलो वाटर के लिये उपयुक्त सोनार सिस्टम से सुसज्जित है।
- इसे विशेष रूप से उथले समुद्री क्षेत्रों में संचालन तथा पानी के नीचे मौजूद खतरों का प्रभावी पता लगाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

प्रणोदन प्रणाली:

- लगभग 77 मीटर लंबाई वाला यह पोत वाटरजेट प्रणोदन प्रणाली से संचालित होने वाले सबसे बड़े भारतीय नौसैनिक युद्धपोतों में शामिल है।

सामरिक महत्त्व:

- यह पोत तटीय निगरानी और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। इससे तटीय क्षेत्र में भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूती मिलती है।

स्वदेशीकरण का पक्ष:

- यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमता में हो रही निरंतर वृद्धि और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल उपयोग को प्रतिबिंबित करती है।

भारत में पहली 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी

चर्चा में क्यों ?

भारतीय सेना अस्पताल, दिल्ली कैंट द्वारा iStent के साथ भारत की पहली 3D फ्लेक्स एक्ववस एंजियोग्राफी का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है, जो ग्लूकोमा के निदान और उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

प्रयुक्त प्रौद्योगिकी:

- यह प्रक्रिया स्टैंड-माउंटेड स्पेक्ट्रलिस प्रणाली तथा 3D ऑपरेंटिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए सम्पन्न की गई, जिससे सटीक इमेजिंग और न्यूनतम इनवेसिव ग्लूकोमा सर्जरी संभव हो सकी।

iStent डिवाइस:

- यह ग्लूकोमा रोगियों में आँख के जलीय द्रव के बहिर्वाह को सुगम बनाने तथा अंतःनेत्र दबाव को कम करने के उद्देश्य से प्रत्यारोपित किया जाने वाला एक सूक्ष्म चिकित्सकीय उपकरण है।

महत्त्व:

- इस उन्नत तकनीक से नेत्र शल्य चिकित्सा में सटीकता, सुरक्षा और उपचार परिणामों में उल्लेखनीय सुधार होता है।

ग्लूकोमा:

- यह नेत्र विकारों का एक समूह है, जिसमें अत्यधिक अंतःनेत्र दबाव के कारण ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुँचती है और समय पर उपचार न होने पर दृष्टि हानि का जोखिम बढ़ जाता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के 25 वर्ष

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार वर्ष 2025 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की 25वीं वर्षगाँठ मना रही है, जो ग्रामीण संपर्कता और अवसंरचना विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित करती है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **प्रारंभ:** यह योजना 25 दिसंबर, 2000 को प्रारंभ की गई।
- ◆ **बजटीय सहायता:** वर्ष 2025-26 में ग्रामीण संपर्कता प्रयासों को जारी रखने हेतु लगभग 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- ◆ **उद्देश्य:** उन ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना, जो पहले पूरी तरह असंबद्ध थीं।
- ◆ **वित्त पोषण:** केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 लागत-साझाकरण अनुपात अपनाया जाता है, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिये यह अनुपात 90:10 है।
- ◆ **PMGSY-IV योजना:** चरण IV (2024-29) के तहत 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिये 62,500 किमी. सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 70,125 करोड़ रुपये है।
- ◆ **प्रगति:** योजना की शुरुआत के बाद से लगभग 8,25,114 किमी ग्रामीण सड़कों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से लगभग 7,87,520 किमी (95-96%) दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो चुकी हैं।
- ◆ **उन्नत निगरानी प्रणाली:** OMMAS (ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली), e-MARG (PMGSY के तहत ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव), GPS ट्रैकिंग और त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, जिससे कार्यान्वयन की पारदर्शिता तथा स्थायित्व बढ़ता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भारत में तीन नई एयरलाइंस

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने भारतीय विमानन क्षेत्र में प्रवेश के लिये तीन नई एयरलाइंस- शंख एयर, अल हिंद एयर तथा फ्लाई एक्सप्रेस को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रदान किये हैं।

मुख्य बिंदु

- ◆ **नियामकीय स्वीकृति:** यह NOC नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जो किसी भी नई एयरलाइन के परिचालन की प्रारंभिक वैधानिक शर्त होती है।
- ◆ **अगला चरण:** NOC प्राप्त करने के पश्चात, संबंधित एयरलाइंस अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं, जो वाणिज्यिक उड़ानों के लिये अनिवार्य है।
- ◆ **परिचालन:** इन एयरलाइंस द्वारा वर्ष 2026 से वाणिज्यिक उड़ान संचालन प्रारंभ किये जाने की संभावना है।
- ◆ **एयरलाइंस का स्वरूप:** प्रस्तावित एयरलाइंस को कम लागत और क्षेत्रीय केंद्रित मॉडल पर विकसित किये जाने की योजना है।
- ◆ **द्वयाधिकार का अंत:** यह पहल भारतीय विमानन क्षेत्र में व्याप्त अत्यधिक एकाधिकार को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ वर्तमान में इंडिगो (लगभग 65%) और एयर इंडिया (लगभग 27%) मिलकर 90% से अधिक यात्री यातायात को नियंत्रित करती हैं।
- ◆ **क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा:** नई एयरलाइंस का प्रवेश द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शहरों तक हवाई संपर्क के विस्तार के सरकारी उद्देश्य के अनुरूप है तथा यह उड़ान (UDAN) क्षेत्रीय संपर्क योजना के व्यापक लक्ष्यों को भी सुदृढ़ करता है।

कैंसर उपचार अवसंरचना हेतु NTPC-GCRI समझौता ज्ञापन (MoA)

चर्चा में क्यों ??

NTPC पश्चिमी क्षेत्र ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के तहत रेडियोथेरेपी सेवाओं के उन्नयन के लिये गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान (GCRI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु

- ◆ **उद्देश्य:** अहमदाबाद स्थित सिद्धपुर सैटेलाइट सेंटर में उच्च-ऊर्जा लिनियर एक्सलेरेटर (LINAC) की खरीद और स्थापना के माध्यम से रेडियोथेरेपी सेवाओं को सुदृढ़ करना।
- ◆ **वित्तपोषण:** क्षमता उन्नयन के लिये NTPC ने अपनी CSR पहल के अंतर्गत ₹23.16 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
- ◆ **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** इस सहायता से उन्नत और परिष्कृत रेडियोथेरेपी उपकरणों की खरीद व स्थापना संभव होगी, जिससे आधुनिक कैंसर उपचार क्षमताओं में सुधार होगा।
- ◆ **CSR फोकस:** यह पहल समावेशी विकास के प्रति NTPC की प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा सार्थक CSR हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करते हुए सतत विकास लक्ष्य-3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) में योगदान देती है।
- ◆ **क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र:** GCRI को सुदृढ़ करने से रोगियों के आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOOPE) में कमी आएगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लनिंग
ऐप



IIT मद्रास ने ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ **उद्देश्य:** यह फाउंडेशन IIT मद्रास को विश्व का पहला **बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय** बनाने की दिशा में कार्य करेगा, जिससे उसके वैश्विक शोध, शिक्षा, नवाचार और सहयोग के क्षेत्र का विस्तार हो सके।
- ◆ **केंद्रित क्षेत्र:** प्रमुख क्षेत्रों में डेटा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, साइबर सुरक्षा, मोबिलिटी, ऊर्जा एवं जल प्रणालियाँ, स्वास्थ्य तकनीक और हरित तकनीक शामिल हैं।
- ◆ **रणनीतिक विस्तार:** प्रारंभिक वैश्विक उपस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, दुबई और मलेशिया सहित कई देशों में स्थापित की जाएगी।
- ◆ **महत्त्व:** यह पहल भारतीय नवाचारों को वैश्विक बाजारों तक पहुँचाने में सहायता करेगी और तकनीकी साझेदारी एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से व्यावसायीकरण को तीव्र करेगी।
- ◆ **उत्सव एकीकरण:** डॉ. जयशंकर ने IITM फेस्टिवल पखवाड़े का भी उद्घाटन किया, जिसमें शास्त्र (तकनीकी उत्सव) और सारंग (सांस्कृतिक उत्सव) के साथ ओपन हाउस एक्सेस शामिल है।

कलाई-II जलविद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने अरुणाचल प्रदेश में 1,200 मेगावाट कलाई-II जलविद्युत परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) की सिफारिश की है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **परियोजना विवरण:** 1,200 मेगावाट कलाई-II जलविद्युत परियोजना लोहित नदी पर प्रस्तावित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के हवाई गाँव में THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
 - यह एक **रन-ऑफ-रिवर (Run-of-River)** प्रकार की परियोजना है, जिसमें नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करते हुए स्वच्छ बिजली उत्पादन के लिये सीमित जल भंडारण शामिल है।
 - **लोहित नदी:** ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है।
- ◆ **EIA विवाद:** पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों ने EIA रिपोर्ट की आलोचना की क्योंकि इसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त **व्हाइट बेलीड हेरान (Ardea insignis)** की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था।
- ◆ **व्हाइट बेलीड हेरान:**
 - **व्हाइट बेलीड हेरान, कम व्यवधान वाले मुक्त प्रवाही नदी क्षेत्रों में रहना पसंद करता है और मुख्य रूप से तीव्र बहाव वाले स्थानों में मछली खाता है।**
 - इसकी उपस्थिति लोहित नदी जलक्षेत्र में दर्ज की गई है, जिसमें **कमलांग और नामदफा टाइगर रिजर्व** शामिल हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- IUCN स्थिति: व्हाइट बेलीड हेरान को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
- WPA स्थिति: इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है।
- ♦ पर्यावरणीय चिंताएँ: आलोचकों का तर्क है कि जलविद्युत बाँध और अन्य अवसंरचनाएँ महत्वपूर्ण नदी पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचा सकती हैं, जिससे व्हाइट बेलीड हेरान जैसी प्रजातियों का निवास स्थान घट सकता है, उनके वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है तथा मछली की संख्या कम हो सकती है।

उपराष्ट्रपति ने किया 'सिंग, डांस एंड लीड' पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 'सिंग, डांस एंड लीड: लीडरशिप लेसनस फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद' पुस्तक का विमोचन किया।

मुख्य बिंदु

- ♦ लेखक: यह पुस्तक हिंदोल सेनगुप्ता द्वारा लिखी गई है।
- ♦ केंद्रबिंदु: इसका केंद्रबिंदु मूल्य-आधारित नेतृत्व पर आधारित है।
- ♦ दर्शन: यह नैतिक नेतृत्व, नैतिक स्पष्टता, सेवा भाव और आंतरिक अनुशासन पर बल देती है।
- ♦ प्रेरणास्रोत: इसमें इस्कॉन के संस्थापक ए. सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व के सूत्र प्रस्तुत किये गए हैं।
- ♦ मुख्य संदेश: नेतृत्व अधिकार पर आधारित होने के बजाय समावेशी, आनंदपूर्ण और विनम्रता में निहित होना चाहिये।

दिल्ली सरकार ने RBI के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों ?

दिल्ली सरकार ने वित्तीय शासन और राजकोषीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु

- ♦ RBI की भूमिका: यह समझौता दिल्ली सरकार के लिये RBI को आधिकारिक बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।
- ♦ MoU के अंतर्गत कार्य: RBI राज्य विकास ऋणों (SDLs) के माध्यम से बाजार उधारी का प्रबंधन करेगा, अधिशेष नकदी का स्वतः निवेश करेगा, पेशेवर नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करेगा और कम लागत वाली तरलता सुविधाओं तक पहुँच उपलब्ध कराएगा।
- ♦ पूंजीगत व्यय: बाजार उधारी से जुटाए गए धन का उपयोग केवल पूंजीगत व्यय के लिये किया जाएगा। प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों में यमुना पुनर्जीवन, जल आपूर्ति, परिवहन और स्वास्थ्य अवसंरचना शामिल हैं।
- ♦ ऐतिहासिक सुधार: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस MoU को दिल्ली की वित्तीय शासन प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार बताया, जो वर्षों से चली आ रही तदर्थ और महँगी वित्तीय प्रथाओं को समाप्त करेगा।
- ♦ लाभ: RBI की प्रणालियों से एकीकृत होने पर दिल्ली सरकार अब प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर धन जुटा सकेगी और अधिशेष धन का कुशल प्रबंधन कर सकेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ♦ राजकोषीय अनुशासन: इस कदम से दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति में राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता मजबूत होने की उम्मीद है।

पिपरावा के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

भारत ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें देश की बौद्ध विरासत और आध्यात्मिक धरोहर को प्रदर्शित किया गया।

मुख्य बिंदु

- ♦ शीर्षक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “प्रकाश और कमल: जागृत व्यक्ति के अवशेष” शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- ♦ अवशेषों का महत्त्व: ये पवित्र अवशेष 125 वर्षों के बाद यूनाइटेड किंगडम से भारत वापस लाए गए।
- ♦ आयोजन स्थल: प्रदर्शनी ऐतिहासिक राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर, नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- ♦ खोज: पिपरावा के अवशेष वर्ष 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरावा गाँव में स्थित एक बौद्ध स्तूप से उत्खनन के दौरान प्राप्त किये गए थे।
- ♦ बौद्ध संबंध: बौद्ध विरासत को वैश्विक स्तर पर संरक्षित करने के भारत के प्रयास थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया और रूस जैसे देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु आकर्षित होते हैं।
- ♦ शास्त्रीय भाषा: बुद्ध की शिक्षाएँ मूल रूप से पाली भाषा में थीं और भारत पाली को वर्ष 2024 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देते हुए वैश्विक स्तर पर इसको बढ़ावा दे रहा है।
- ♦ महत्त्व: यह प्रदर्शनी बौद्ध विरासत के संरक्षक के रूप में भारत की भूमिका को सशक्त करती है और शांति, सद्भाव तथा वैश्विक सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करती है।

भारत में IICDEM-2026 का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (IICDEM)-2026 का आयोजन करेगा।

मुख्य बिंदु

- ♦ आयोजक: यह सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के तत्वाधान में भारत इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IICDEM) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- ♦ उद्देश्य: चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक शासन में ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने के लिये एक मंच प्रदान करना।
- ♦ विषय: सम्मेलन का विषय है “Democracy for an inclusive, peaceful, resilient and sustainable world” अर्थात “एक समावेशी, शांतिपूर्ण, अनुकूल और सतत विश्व के लिये लोकतंत्र”।
- यह वर्ष 2026 के लिये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान (अंतर्राष्ट्रीय IDEA) के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ सत्र: सम्मेलन में चुनाव प्रबंधन निकाय (EMB) के नेताओं का पूर्ण सत्र, कार्य समूह की बैठकें, ECINet का शुभारंभ और वैश्विक चुनावी मानकों और नवाचारों पर विषयगत चर्चाएँ शामिल होंगी।
- ◆ नेतृत्व: सम्मेलन का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे।
 - चुनाव प्रबंधन निकाय (EMB): यह एक प्राधिकरण है, जो किसी देश में चुनावों के आयोजन, प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी होता है।

धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर (NDWBF) 2026 का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ आयोजक: यह पुस्तक मेला राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (NBT) भारत द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया गया है।
- ◆ थीम: NDWBF 2026 की थीम है " भारतीय सैन्य इतिहास: वीरता और बुद्धिमत्ता @75", जो भारत के सशस्त्र बलों की भूमिका और विरासत को दर्शाती है।
- ◆ पुस्तक विमोचन: उद्घाटन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने 'द सागा ऑफ कुडोपाली: 1857 की अनकही कहानी' पुस्तक का हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं और स्पेनिश भाषा में विमोचन किया। यह पुस्तक वीर सुरेंद्र साई और संबलपुर के शहीदों को सम्मानित करती है।
- ◆ अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी: कतर और स्पेन सहित कई देशों ने मेले में भाग लिया।
 - फोकस देश: कतर (प्रदर्शनियों और साहित्यिक आदान-प्रदान का मुख्य केंद्र)
 - सहभागी देश: स्पेन (सांस्कृतिक और साहित्यिक सहभागिता)
- ◆ पठन संस्कृति को बढ़ावा: यह पुस्तक मेला छात्रों, शोधकर्ताओं और आम जनता में पठन संस्कृति, ज्ञान-वितरण, बहुभाषिकता तथा वैश्विक साहित्यिक संवाद के महत्त्व को रेखांकित करता है।

'आशा वैन' मोबाइल यूनिट

चर्चा में क्यों ?

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिये एक मोबाइल 'आशा वैन' का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ सुविधा: आशा वैन एक मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट है, जो
 - EVA-प्रो डायग्नोस्टिक्स, एक मैमोग्राफी मशीन और
 - विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिये टेली-कंसल्टेशन सेवाओं से सुसज्जित है।।
- ◆ स्क्रीन किये जाने वाले कैंसर के प्रकार: यह अल्ट्रा-आधुनिक उपकरणों की सहायता से फेफड़े, मुँह, रक्त, गर्भाशय ग्रीवा, अग्न्याशय, यकृत, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर सहित कई प्रकार के कैंसर का ऑन-साइट स्क्रीनिंग करने में सक्षम बनाता है।
- ◆ सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्य में समर्थन: यह पहल प्रधानमंत्री के 'हेल्थ एंड वेलनेस फॉर ऑल' विज्ञान को सहयोग प्रदान करती है, जिससे प्रारंभिक निदान और उपचार के परिणामों में सुधार होता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ रेड क्रॉस को सुपर्दगी: आशा वैन को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की भावनगर शाखा को सौंप दिया गया।
- ◆ ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान: यह पहल उन्नत कैंसर स्क्रीनिंग सेवाओं को गाँवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचाती है, जिससे दूरी तथा सीमित स्वास्थ्य सुविधा की बाधाओं को कम किया जा सकता है।

IIT मद्रास में सुपरकंप्यूटर परम शक्ति लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IIT मद्रास में परम शक्ति सुपरकंप्यूटर का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ क्षमता: यह 3.1 पेटाफ्लॉप प्रणाली है, जो प्रति सेकंड 3.1 क्वाड्रिलियन से अधिक गणनाएँ कर सकती है।
- ◆ स्वदेशी तकनीक: इसे राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत C-DAC की RUDRA सर्वर शृंखला और स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक (AlmaLinux) का उपयोग करके बनाया गया है।
- ◆ अनुप्रयोग: इसका उपयोग जलवायु मॉडलिंग, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, दवा खोज और उन्नत निर्माण में अनुसंधान के लिये किया जाएगा।
- ◆ NSM की उपलब्धि: यह भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित 37वाँ सुपरकंप्यूटर है।
- ◆ कुशलता: इसमें 1.2 से 1.4 का पावर यूसेज एफेक्टिवनेस (PUE) है, जो इसे अत्यंत ऊर्जा-कुशल बनाता है।
- ◆ शीर्ष समकक्ष: जबकि PARAM SHAKTI शक्तिशाली है, भारत का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर अभी भी C-DAC पुणे में AIRAWAT-PSAI (13.17 PF) है।

अकासा एयर IATA में पाँचवीं भारतीय सदस्य के तौर पर शामिल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अकासा एयर ने आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) की सदस्यता प्राप्त की।

मुख्य बिंदु

- ◆ पूर्वापेक्षा: इस एयरलाइन ने दिसंबर 2025 में अनिवार्य IATA ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट (IOSA) को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो एयरलाइनों के लिये एक सख्त, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सुरक्षा और परिचालन मानक है।
- ◆ समान समूह: अकासा एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइसजेट के साथ केवल भारतीय IATA सदस्यों में शामिल हुई।
- ◆ लाभ: सदस्यता से वैश्विक विश्वसनीयता, डिजिटल परिवर्तन में भागीदारी और भविष्य में इंटरलाइन/कोडशेयर व्यवस्था की सुविधा मिलती है।
- ◆ स्केल: वर्ष 2022 में लॉन्च के बाद अकासा ने 31 बोइंग 737 मैक्स विमानों के बेड़े के साथ 23 मिलियन से अधिक यात्रियों की सेवा की है।
- ◆ IATA पहुँच: यह लगभग 360 एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक हवाई यातायात का 80% हिस्सा हैं।
- ◆ आर्थिक प्रभाव: भारत में विमानन क्षेत्र 7.7 मिलियन नौकरियों का समर्थन करता है और GDP में लगभग \$53.6 बिलियन का योगदान देता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



अरुणाचल प्रदेश में 1720 मेगावाट कमला जलविद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों ?

कमला नदी (सुबनसिरी की एक सहायक नदी) पर 1720 मेगावाट का कमला प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश को भारत का 'पावर हाउस' बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **क्षमता:** 1720 मेगावाट का उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रिड को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना है।
- ❖ **परियोजना का स्वरूप:** यह एक स्टोरेज-कम-रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है, जिसे ब्रह्मपुत्र बेसिन की उच्च हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्षमता का उपयोग करने के लिये डिजाइन किया गया है।
- ❖ **रणनीतिक लक्ष्य:** यह वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिये केंद्र सरकार के विज्ञान का एक हिस्सा है।
- ❖ **नदी बेसिन:** यह परियोजना कामले जिले में स्थित है।
- ❖ **उत्तर-पूर्व ग्रिड:** यह परियोजना, सुबनसिरी लोअर परियोजना के साथ क्षेत्रीय बुनियादी अवसंरचना के लिये महत्वपूर्ण है और उत्तर भारत की उच्चतम विद्युत मांग को पूरा करने में सहायक है।
- ❖ **पर्यावरणीय मंजूरी:** सभी प्रमुख हिमालयी परियोजनाओं की तरह इसे भूकंपीय सुरक्षा और स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव के लिये कड़ी निगरानी के अधीन रखा गया है।

अरलम तितली अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

केरल सरकार ने कन्नूर जिले के अरलम वन्यजीव अभयारण्य का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **सूचना:** इस नाम परिवर्तन की आधिकारिक सूचना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत जारी की गई।
- ❖ **कारण:** क्षेत्र में तितली प्रजातियों की समृद्ध विविधता और संख्या के कारण तथा उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा एवं संवर्द्धन की आवश्यकता के चलते।
 - ⦿ **तितली विविधता:** अरलम में लगभग 266 तितली प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो केरल की कुल तितली विविधता का 80% से अधिक हैं।
 - ⦿ **स्थानीय प्रजातियाँ:** अरलम में 27 प्रजातियाँ केवल पश्चिमी घाटों में ही पाई जाती हैं।
- ❖ **WP अधिनियम के तहत सुरक्षा:** अरलम में दर्ज 6 तितली प्रजातियाँ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध हैं।
- ❖ **ऐतिहासिक स्थिति:** अरलम क्षेत्र को मूल रूप से वर्ष 1984 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
- ❖ **वैश्विक महत्त्व:** यह अभयारण्य पश्चिमी घाटों का हिस्सा होने के नाते वैश्विक पारिस्थितिक महत्त्व रखता है, जिसे UNESCO ने विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ♦ सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव: नाम परिवर्तन से जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने, पर्यावरणीय शिक्षा, इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने और तितलियों की संख्या की सुरक्षा में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 में MSME के लिये PFRDA NPS आउटरीच

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राजकोट, गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान MSME क्षेत्र के लिये एक विशेष NPS आउटरीच सत्र आयोजित किया।

मुख्य बिंदु

- ♦ उद्देश्य: MSME मालिकों और उनके कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अपनाने के लिये प्रोत्साहित करके सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करना।
- ♦ कॉर्पोरेट मॉडल पर ध्यान: PFRDA ने 'NPS कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल' को उजागर किया, जो MSME को कर्मचारियों को न्यूनतम प्रशासनिक बोझ के साथ संरचित सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने की अनुमति देता है।
- ♦ वित्तीय साक्षरता: यह सत्र गुजरात के औद्योगिक केंद्रों में असंगठित और अर्द्ध-संगठित श्रमिक वर्ग के लिये पेंशन कवरेज के अंतर को कम करने का लक्ष्य रखता है।
- ♦ सम्मानजनक वृद्धावस्था: MSME भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और व्यवसाय मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच सेवानिवृत्ति बचत की संस्कृति को बढ़ावा देना भविष्य की वित्तीय असुरक्षा को कम करने और सम्मानजनक वृद्धावस्था को सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है।
- ♦ MSME का योगदान: MSME क्षेत्र भारत के GDP में लगभग 30% का योगदान देता है और 'पेंशन वाले भारत' लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
- ♦ PFRDA: यह एक सांविधिक नियामक निकाय है, जिसे वर्ष 2013 के PFRDA अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, ताकि भारत में पेंशन क्षेत्र को बढ़ाया और नियंत्रित किया जा सके।
- ♦ NPS संरचना: यह एक स्वैच्छिक, परिभाषित योगदान वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इसे PRAN ((परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) के आधार पर नियंत्रित किया जाता है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे मेघालय उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने मेघालय उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिससे वे राज्य के इतिहास में इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला बन गईं।

मुख्य बिंदु

- ♦ नियुक्ति: यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की अनुशंसा के आधार पर की गई।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ मेघालय उच्च न्यायालय: यह 23 मार्च 2013 को, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में संशोधन के बाद स्थापित किया गया था।
- प्रथम मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति टी. मीना कुमारी मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं, जिन्होंने न्यायालय की स्थापना के साथ ही 23 मार्च 2013 को शपथ ली थी।
- ◆ नियुक्ति प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके की जाती है।
- ◆ महत्व: मेघालय अपने मातृसत्तात्मक सामाजिक ढाँचे के लिये जाना जाता है, जिससे महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के न्यायिक नेतृत्व के लिये विशेष रूप से प्रतीकात्मक बन जाती है।
- ◆ लैंगिक समानता: वर्ष 2026 में भारत उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के प्रयास जारी रखे हुए है, जहाँ वर्तमान में महिलाएँ कुल न्यायाधीश संख्या का 15% से भी कम हैं।

'नशा मुक्त परिसर' अभियान का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

उप-राष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने 11 जनवरी, 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में 'नशा मुक्त परिसर अभियान' का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ विज्ञान: यह अभियान नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य शिक्षा संस्थानों में युवाओं के बीच मादक पदार्थों के सेवन को रोकना है।
- ◆ रणनीति: इसमें छात्र-नेतृत्व वाले 'एंटी-ड्रग क्लब' का गठन और विश्वविद्यालय स्वास्थ्य प्रणाली में काउंसलिंग सेवाओं का समावेश शामिल है।
- ◆ उप-राष्ट्रपति का संबोधन: उन्होंने जोर दिया कि विकसित भारत @2047 तभी संभव है जब युवा स्वस्थ, अनुशासित और नशे से मुक्त हों।
- ◆ शुरू किये गए प्लेटफॉर्म: इस अभियान के तहत एक समर्पित ई-प्रतिज्ञा प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ताकि पूरे देश के छात्र नशा मुक्त परिसर के लिये प्रतिज्ञा ले सकें।
- ◆ नशा मुक्त भारत अभियान: इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया तथा यह भारत के 272 सबसे संवेदनशील जिलों पर केंद्रित है।
- ◆ अनुच्छेद 47: भारत का संविधान (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) राज्य को निर्देश देता है कि मादक पेय और ड्रग्स के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे।
- ◆ NCB की भूमिका: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) इन कैंपस अभियानों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि शैक्षणिक क्षेत्रों के आसपास स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं का पता लगाकर उन्हें समाप्त किया जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



MoEFCC ने लॉन्च किया संस्थागत समन्वय हेतु 'NIRANTAR' प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (MoEFCC) ने जनवरी 2026 में NIRANTAR प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करने के लिये एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य बिंदु

- ◆ **NIRANTAR डैशबोर्ड:** यह एक डिजिटल एकीकृत डैशबोर्ड है, जिसे MoEFCC के तहत आने वाले संस्थानों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB/SPCBs), भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के बीच समन्वय मजबूत करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- ◆ **रीयल-टाइम मॉनिटरिंग:** यह प्लेटफॉर्म पर्यावरण मंजूरी, वनाग्नि अलर्ट और वन्यजीव तस्करी डेटा को रीयल-टाइम में ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।
- ◆ **डेटा इंटीग्रेशन:** इसका उद्देश्य 'सिलो-आधारित' कार्यप्रणाली को समाप्त करना है, जिससे विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के जलवायु डेटा को एक ही विंडो के तहत नीति निर्माण के लिये उपलब्ध कराया जा सके।
- ◆ **MoEFCC:** यह केंद्र सरकार में पर्यावरण और वनों की नीतियों की निगरानी करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
- ◆ **डिजिटल इंडिया और पर्यावरण:** NIRANTAR, PARIVESH जैसी पूर्व पहलों पर आधारित है, लेकिन यह एजेंसियों के बीच समन्वय को सुनिश्चित करने के लिये व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।
- ◆ **सतत विकास:** यह मंच डेटा-आधारित संरक्षण सुनिश्चित करके SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) और SDG 15 (भूमि पर जीवन) को प्राप्त करने का एक साधन है।

विशाखापत्तनम में भारतीय प्रकाशस्तंभ महोत्सव का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

तीसरा भारतीय प्रकाशस्तंभ महोत्सव 9 जनवरी, 2026 को विशाखापत्तनम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटित किया गया।

मुख्य बिंदु

- ◆ **पर्यटन प्रोत्साहन:** यह महोत्सव ऐतिहासिक प्रकाशस्तंभ को जीवंत पर्यटन केंद्रों में बदलने का लक्ष्य रखता है, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिले।
- ◆ **नई परियोजनाएँ:** विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश का पहला प्रकाशस्तंभ म्यूज़ियम और असम के नदी क्षेत्र में चार नए प्रकाशस्तंभ बनाने की योजनाएँ प्रस्तुत की गईं।
- ◆ **MGM पार्क:** कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी शामिल थीं, जो 'सिटी ऑफ़ डेस्टिनी' की समुद्री विरासत को उजागर करती हैं।
- ◆ **मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030:** यह महोत्सव मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और पर्यटन-आधारित तटीय विकास के लिये सरकार की रणनीति के अनुरूप है।
- ◆ **सागरमाला कार्यक्रम:** प्रकाशस्तंभ का कायाकल्प, बंदरगाह-आधारित विकास और तटीय समुदाय के सशक्तीकरण का एक उप-घटक है।
- ◆ **महत्त्व:** यह प्रकाशस्तंभ पर्यटन की अवधारणा को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पर्यटन विकल्प के रूप में मजबूत करता है, जिससे स्थानीय आजीविका, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भारत की विस्तृत तटीय रेखा के आसपास सतत पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नमामि गंगे के तहत जलीय जैव विविधता पहल शुरू की

चर्चा में क्यों ?

14 जनवरी, 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने नमामि गंगे के अंतर्गत जल जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं की एक शृंखला का उद्घाटन भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून में किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ **नया केंद्र:** गंगा और अन्य नदियों के लिये **एक्वा लाइफ कंज़र्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर** नामक एक समर्पित राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया है, जो स्वच्छ जल की जैव विविधता के वैज्ञानिक मॉनिटरिंग, अनुसंधान और नीतिगत मार्गदर्शन को समर्थन देगा।
- **नई सुविधाएँ:** केंद्र में **इकोटॉक्सिकोलॉजी, एक्वाटिक इकोलॉजी, स्पैशियल इकोलॉजी** और **माइक्रोप्लास्टिक विश्लेषण** के लिये उन्नत प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।
- ◆ **डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस:** TSAFI द्वारा संचालित विशेष रूप से सुसज्जित डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस शुरू की गई, जो संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन के लिये तीव्र और वैज्ञानिक आपातकालीन सहायता प्रदान करेगी।
- ◆ **इंडियन स्किमर संरक्षण परियोजना:** **बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS)** के सहयोग से इस दुर्लभ पक्षी प्रजाति **इंडियन स्किमर** के लिये एक संरचित संरक्षण योजना औपचारिक रूप से शुरू की गई, जो **गंगा बेसिन** में इसके आवास संरक्षण पर केंद्रित है।
- ◆ **प्रजाति संरक्षण:** गंगा डॉल्फिन और हिलसा मछली के लिये नई संरक्षण योजनाएँ शुरू की गईं, जिनका उद्देश्य इनके प्राकृतिक आवास का पुनर्स्थापन है।
 - **जैवविविधता:** गंगा बेसिन में **2,500 से अधिक** जीव और वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- ◆ **नमामि गंगे चरण II:** अब ध्यान केवल 'अविरल' (निरंतर प्रवाह) और 'निर्मल' (स्वच्छ प्रवाह) से आगे बढ़कर **ज्ञान गंगा (अनुसंधान)** तथा **अर्थ गंगा (आर्थिक स्थिरता)** पर भी केंद्रित है।
- ◆ **महत्त्व:** यह केंद्र दीर्घकालिक प्रजाति निगरानी, स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी पर अनुसंधान, नीतिगत समर्थन तथा वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित निर्णय-निर्माण के लिये एक प्रमुख वैज्ञानिक हब के रूप में कार्य करेगा।

गुजरात में हाई-रिस्क पैथोजेन हेतु भारत की पहली राज्य-वित्तपोषित BSL-4 लैब

चर्चा में क्यों ?

गुजरात में भारत की पहली राज्य-वित्तपोषित बायोसेफ्टी लेवल-4 (BSL-4) प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई। यह सुविधा भारत में उच्च-संरक्षण अनुसंधान के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पहले केवल **केंद्रीय सरकारी संस्थानों** तक सीमित था।

मुख्य बिंदु

- ◆ **समेकित परिसर:** यह लैब बहु-स्तरीय संरचना के रूप में तैयार की गई है, जिसमें **BSL-4, BSL-3 और BSL-2** मॉड्यूल शामिल हैं।
- ◆ **पशु अनुसंधान:** महत्वपूर्ण रूप से, इसमें **ABSL-3 और ABSL-4** (एनिमल बायोसेफ्टी लेवल) मॉड्यूल भी शामिल हैं, जो वैज्ञानिकों को घातक वायरस के जीवित प्राणियों के साथ परस्पर क्रिया का अध्ययन करने में सक्षम बनाते हैं, जो वैक्सीन विकास की एक आवश्यक प्रक्रिया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लनिंग
ऐप



- ❖ **वित्तपोषण मॉडल:** भारत की मौजूदा BSL-4 लैब्स (जैसे पुणे स्थित NIV) जो ICMR द्वारा केंद्रीय रूप से वित्तपोषित हैं, उनसे अलग यह परियोजना पहली ऐसी पहल है जिसे किसी राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और प्रबंधित किया जा रहा है।
- ❖ **समयरेखा:** COVID-19 महामारी से स्थानीय स्तर पर निदान क्षमता और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का एहसास होने के बाद, इस उच्च-सुरक्षा केंद्र की योजना का प्रारंभ वर्ष 2022 के मध्य में किया गया।
- ❖ **महामारी तैयारी:** यह सुविधा गुजरात को 'डिज़ीज़ X' या किसी नए वायरल प्रकोप की पहचान और अनुसंधान स्थानीय स्तर पर करने में सक्षम बनाएगी, जिससे सभी नमूनों को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रतिक्रिया समय में महत्वपूर्ण बचत होगी।
- ❖ **वन हेल्थ दृष्टिकोण:** एनिमल बायोसेफ्टी (ABSL) मॉड्यूल को एकीकृत करके, यह लैब 'वन हेल्थ' फ्रेमवर्क का समर्थन करती है, जो मानवीय, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संबंध को स्वीकार करती है तथा जूनोटिक रोग प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बायोसेफ्टी लेवल (BSL)

- ❖ **BSL-1 और BSL-2:** इनका उपयोग मध्यम जोखिम वाले रोगजनकों (जैसे *E. coli* या सामान्य फ्लू) के लिये किया जाता है, जो मनुष्यों में हल्की बीमारी उत्पन्न करते हैं।
 - ❖ **BSL-3:** इसका उपयोग स्वदेशी या विदेशी रोगजनकों के लिये किया जाता है, जो गंभीर या संभावित रूप से घातक बीमारी का कारण बन सकते हैं और वायु के माध्यम से फैल सकते हैं (उदाहरण: क्षय रोग, SARS-CoV-2)।
 - ❖ **BSL-4 (उच्च-संरक्षण स्तर):** यह स्तर अत्यंत खतरनाक एवं दुर्लभ रोगजनकों के लिये होता है, जो जीवन-घातक बीमारी का उच्च जोखिम उत्पन्न करते हैं, जिनके लिये कोई ज्ञात टीका या उपचार उपलब्ध नहीं होता और जो एरोसोल के माध्यम से आसानी से फैल सकते हैं।
- 🕒 उदाहरण: इबोला, मारबर्ग और निपाह वायरस।

विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी की

चर्चा में क्यों ?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी की है, जो वैश्विक जोखिम धारणाओं और संभावित खतरों के उसके वार्षिक मूल्यांकन का 21वाँ संस्करण है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **प्रतिस्पर्धा का युग:** रिपोर्ट 2026 में वैश्विक जोखिम परिदृश्य की प्रमुख विशेषता के रूप में 'अनिश्चितता' को रेखांकित करती है और इस तर्क पर प्रकाश डालती है कि विश्व 'प्रतिस्पर्धा के युग' में प्रवेश कर रहा है, जहाँ भू-राजनीतिक और आर्थिक टकराव सहयोग को पीछे छोड़ रहे हैं तथा पारंपरिक बहुपक्षीय प्रणालियाँ दबाव में हैं।
- ❖ **शीर्ष अल्पकालिक खतरा:** तात्कालिक परिदृश्य (2028 तक) में आर्थिक और भू-राजनीतिक तनावों ने पर्यावरणीय चिंताओं को तात्कालिकता के मामले में पीछे छोड़ दिया है।
- 🕒 **भूराजनीतिक-आर्थिक टकराव:** वर्ष 2025 में तीसरे स्थान से यह अब पहले स्थान पर आ गया है। इसमें शुल्क, प्रतिबंध और निवेश सीमाओं के माध्यम से व्यापार का 'हथियारीकरण' शामिल है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- गलत सूचना और दुष्प्रचार: AI द्वारा बनाए गए डीपफेक्स के बढ़ते प्रसार के कारण, विशेषकर चुनावी अवधियों में सामाजिक स्थिरता पर गंभीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं।
- सामाजिक ध्रुवीकरण: लोकतांत्रिक प्रणालियों और सार्वजनिक विश्वास पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।
- अत्यधिक मौसमी घटनाएँ: कम समय की अहमियत के मामले में वे दूसरे से चौथे स्थान पर आ गए हैं। हालाँकि वे दीर्घकालिक समय के लिये सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं।
- ◆ दीर्घकालिक जोखिम (10-वर्षीय परिदृश्य): पर्यावरणीय खतरे आगामी दशक के परिदृश्य में प्रमुख बने हुए हैं, जिनमें अत्यधिक मौसमी घटनाएँ और जैव-विविधता ह्रास को सबसे गंभीर जोखिम के रूप में रैंक किया गया है।
 - विशेष रूप से, AI तकनीकों के प्रतिकूल परिणाम गंभीरता के मामले में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज करते हुए अल्पकालिक सूची में 30वें स्थान से बढ़कर 10-वर्षीय परिदृश्य में 5वें स्थान पर पहुँच गए।
- ◆ भारत के लिये प्रमुख निष्कर्ष: रिपोर्ट ने अगले दो वर्षों में भारत को प्रभावित करने की सबसे अधिक संभावना वाले विशिष्ट 'हॉट स्पॉट' जोखिमों की पहचान की है—
 - साइबर असुरक्षा: भारत में डिजिटल भुगतान और डिजिटल अवसंरचना की तीव्र वृद्धि के कारण इसे शीर्ष जोखिम के रूप में रैंक किया गया है।
 - संपत्ति और आय असमानता: आंतरिक सामाजिक अस्थिरता का प्रमुख कारक है।
 - महत्त्वपूर्ण अवसंरचना और संसाधन सुरक्षा: 'जल सुरक्षा' को एक बड़े विवाद बिंदु के रूप में रेखांकित किया गया है, विशेषकर सिंधु नदी बेसिन के संदर्भ में।
 - आर्थिक बाह्य आघात: वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों और अंतर्राष्ट्रीय शुल्कों के प्रति संवेदनशीलता।

गुजरात ने 'पोषण उड़ान 2026' शुरू किया

चर्चा में क्यों ?

गुजरात ने मकर संक्रांति उत्सव के दौरान 'पोषण उड़ान 2026' की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक उत्सवों और सामुदायिक सहभागिता का उपयोग करते हुए पूरे राज्य में पोषण तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है।

मुख्य बिंदु

- ◆ पहल: 'पोषण उड़ान 2026' पूरे राज्य में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिये पतंग उत्सव की लोकप्रियता का उपयोग करता है, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य संदेशों वाली पतंगें उड़ाई जाती हैं।
 - इसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों और माताओं के लिये संतुलित आहार तथा स्वास्थ्य के महत्त्व को रेखांकित करना है।
- ◆ एकीकरण: यह कार्यक्रम आँगनवाड़ी केंद्रों पर ICDS (एकीकृत बाल विकास सेवाओं) के अंतर्गत संचालित किया जाता है।
- ◆ कार्यान्वयन: यह राज्यव्यापी पोषण जागरूकता अभियान गुजरात के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है।
- ◆ फोकस: पहल का मुख्य जोर आहार विविधता, जंक फूड के सेवन को घटाने, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता प्रथाओं पर है ताकि पोषण संबंधी परिणामों में सुधार हो सके।
- ◆ लक्षित समूह: जागरूकता अभियान में स्कूल के बच्चे, किशोरियाँ, गर्भवती और धात्री महिलाएँ तथा स्थानीय समुदाय के अभिकर्ता शामिल होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **स्वास्थ्य हस्तक्षेप:** माताओं और बच्चों के लिये हीमोग्लोबिन परीक्षण, आयरन एवं फोलिक एसिड (IFA) टैबलेट वितरण, BMI (शरीर द्रव्यमान सूचकांक) जाँच तथा व्यक्तिगत पोषण परामर्श जैसी गतिविधियाँ संचालित की गईं।

तमिलनाडु में बनेगा भारत का पहला 'सॉवरेन AI पार्क'

चर्चा में क्यों ?

13 जनवरी, 2026 को तमिलनाडु सरकार ने सर्वम AI के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत चेन्नई में भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क स्थापित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- ◆ **फुल-स्टैक इन्फ्रास्ट्रक्चर:** यह पार्क संपूर्ण AI जीवनचक्र की मेज़बानी करेगा, जिसमें GPU-आधारित विशिष्ट डेटा सेंटर, स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) और एप्लीकेशन-लेयर टूल शामिल होंगे।
- ◆ **भारतीय भाषाओं पर केंद्रित AI:** इस सुविधा का प्रमुख लक्ष्य भारतीय भाषाओं, विशेषकर तमिल भाषा के लिये इंडिक LLMs का विकास करना है ताकि गैर-अंग्रेज़ी भाषी आबादी के लिये डिजिटल अंतराल को कम किया जा सके।
- ◆ **डेटा संप्रभुता:** राज्य के भीतर ही डेटा एवं कंप्यूटिंग क्षमता की मेज़बानी करके यह परियोजना सुनिश्चित करती है कि नागरिकों और सरकार से संबंधित संवेदनशील जानकारी स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही सुरक्षित रहे तथा विदेशी निगरानी या अंतर्राष्ट्रीय कानूनी जटिलताओं से संरक्षित हो।
- ◆ **रणनीतिक सहयोग:** यह पार्क तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी (TNeGA) के सहयोग से प्रबंधित किया जाएगा, ताकि AI को सार्वजनिक सेवा वितरण में एकीकृत किया जा सके।
- ◆ **'सॉवरेन AI':** सॉवरेन AI से तात्पर्य एक देश या राज्य की उस क्षमता से है जिसके माध्यम से वह अपने स्वयं के अवसंरचना, डेटा और मानव संसाधन का उपयोग करके AI विकसित कर सके।
 - **रणनीतिक स्वायत्तता:** इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक अनुकूलन के लिये आवश्यक माना जाता है और यह 'डिजिटल उपनिवेशवाद' को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ◆ **महत्त्व:** यह पहल डिजिटल स्वायत्तता प्राप्त करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है और तमिलनाडु को उच्चस्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक होगी।
 - यह परियोजना केंद्र सरकार के इंडिया AI मिशन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य AI कंप्यूट एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाना है।

इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के तौर पर पहला ONDC ऑर्डर डिलीवर किया

चर्चा में क्यों ?

डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उसने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के लिये लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता के रूप में अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर किया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **लेन-देन:** उद्घाटन ऑर्डर में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के एक स्थानीय विक्रेता से प्राप्त अखरोट की शिपमेंट शामिल थी, जिसे दिल्ली में एक उपभोक्ता तक डिलीवर किया गया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **इंडिया पोस्ट की भूमिका:** पारंपरिक डाक सेवाओं की सीमाओं से आगे बढ़कर **इंडिया पोस्ट** ने लॉजिस्टिक्स की मुख्य जिम्मेदारी सँभाली और दूरदराज क्षेत्रों से पिकअप लेकर महानगर में अंतिम गंतव्य वितरण तक पूरी मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन किया।
- ◆ **एकीकरण:** दिल्लीवरी **इंडिया पोस्ट** के आंतरिक लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर को ONDC के ओपन प्रोटोकॉल के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करके संभव हुई, जिससे **रीयल-टाइम ट्रैकिंग और स्वचालित डिस्पैच** सुनिश्चित हुआ।
- ◆ **लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क:** इंडिया पोस्ट को शामिल करने से ONDC को **1.6 लाख से अधिक डाकघरों तक पहुँच** मिलती है, जिससे सबसे दूरदराज ग्रामीण विक्रेता भी राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच सकते हैं।
- ◆ **समान अवसर:** अब छोटे कारीगर और **MSME** उच्च-गुणवत्ता वाली लॉजिस्टिक्स सेवाओं का प्रतिस्पर्द्धी दरों पर लाभ उठा सकते हैं, जो पहले डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने में एक बड़ी बाधा था।
- ◆ **स्थानीय का समर्थन (Vocal for Local):** यह एकीकरण **वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)** पहल को मजबूती देता है, क्योंकि यह क्षेत्रीय विशिष्टताओं के लिये भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराता है।
- ◆ **वित्तीय समावेशन:** यह ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल भुगतान अपनाने और अपने व्यवसाय को औपचारिक बनाने के लिये प्रोत्साहित करता है, जिससे **विकसित भारत @2047** के लक्ष्य में योगदान मिलता है।

IOA ने नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने स्थानीय स्तर से लेकर उत्कृष्ट स्तर तक भारत की संपूर्ण ओलंपिक प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम (NOEDP) को औपचारिक रूप से शुरू किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ **समेकित ढाँचा:** NOEDP को एक व्यापक राष्ट्रीय ढाँचे के रूप में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य **राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs)** और **राज्य ओलंपिक संघों (SOAs)** के सहयोग से पूरे खेल पारितंत्र में संरचित शैक्षणिक पहलें लागू करना है।
- ◆ **नेशनल ओलंपिक अकादमी (NOA) का पुनर्संक्रियण:** इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आधार अहमदाबाद स्थित **नेशनल ओलंपिक अकादमी (NOA)** का औपचारिक पुनर्संक्रियण है। NOA भारत में **ओलंपिक शिक्षा, अधिगम, अनुसंधान और संवाद** का केंद्रीय केंद्र होगा।
- ◆ **नेतृत्व:** IOA की अध्यक्ष और दिग्गज धाविका **पी. टी. उषा** को NOA की अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित किया गया है, जबकि ओलंपिक पदक विजेता एवं IOA के उपाध्यक्ष **गगन नारंग** को इसका निदेशक नियुक्त किया गया है।
- ◆ **अंतर्राष्ट्रीय अनुरूपता:** NOA, ओलंपिया स्थित **इंटरनेशनल ओलंपिक अकादमी** के साथ सहयोग करेगा ताकि भारत के कार्यक्रम वैश्विक मानकों के अनुरूप हों और ओलंपिक चार्टर का पालन सुनिश्चित करें।
- ◆ **महत्त्व:** ये पहलें एथलीट-केंद्रित ओलंपिक आंदोलन को मजबूत करने पर भारत के नए फोकस को दर्शाती हैं, जिससे खिलाड़ियों को अपने करियर के दौरान नेतृत्व कौशल और शैक्षणिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।

निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में केरल देश में अग्रणी

चर्चा में क्यों ?

केरल 2025 में भारत में निजी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने के मामले में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ◆ केरल की EV नेतृत्व स्थिति: वर्ष 2025 में भारत में निजी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने की दर में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया।
- ◆ व्यक्तिगत EV अपनाने में बढ़त: केरल में लगभग 93.4% EV निजी वाहन (दो-पहिया और चार-पहिया) थे, जो उपभोक्ताओं की मजबूत मांग को दर्शाता है।
 - वाहन पंजीकरण में वृद्धि: वर्ष 2025 में केरल में कुल वाहन पंजीकरण में 12.8% की वृद्धि दर्ज की गई।
 - EV बिक्री के आँकड़े: वर्ष 2025 में केरल में लगभग 80,261 EV बेचे गए।
- ◆ चार्जिंग अवसंरचना: केरल में सार्वजनिक और निजी स्टेशनों सहित व्यापक EV चार्जिंग नेटवर्क मौजूद है।
- ◆ नीति समयरेखा: केरल की EV नीति (2019) ने प्रारंभिक अपनाने, चार्जिंग नेटवर्क और प्रोत्साहनों की मजबूत नींव रखी।
 - सरकारी समर्थन: राज्य की सब्सिडी, कर लाभ और कम पंजीकरण शुल्क ने उपभोक्ताओं को EV अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया।

होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी

चर्चा में क्यों ?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- ◆ स्थान: प्रस्तावित सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा खाड़ी में होप आइलैंड पर बनाई जाएगी।
 - रणनीतिक दूरी: होप आइलैंड, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लगभग 600 किलोमीटर दूर स्थित है, जो भारत का प्रमुख अंतरिक्ष बंदरगाह है।
 - सामुद्रिक लाभ: होप आइलैंड का तटीय स्थान बंगाल की खाड़ी पर लॉन्च मार्गों के लिये रणनीतिक लाभ प्रदान करता है और जनसंख्या पर न्यूनतम जोखिम सुनिश्चित करता है।
- ◆ परियोजना का नाम: यह स्पेस सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक अंतरिक्ष और एयरोस्पेस हब बनाना है।
 - यह आंध्र प्रदेश के उच्च तकनीकी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, नवाचार और औद्योगिक विकास पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।
- ◆ सहयोग: ग्रीनको ग्रुप के साथ।
- ◆ स्पेस इकोसिस्टम विज्ञान: यह सुविधा आंध्र प्रदेश के विज्ञान के अनुरूप है, जो इसे एयरोस्पेस और वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों के हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

हैदराबाद में जनजातीय चिकित्सकों के लिये राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हैदराबाद, तेलंगाना में राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सक निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ◆ शुरुआत स्थल: जनजातीय चिकित्सक कार्यक्रम का आयोजन जनवरी 2026 में कान्हा शांति वनम, हैदराबाद में किया गया, ताकि जनजातीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सके।
- ◆ उद्घाटनकर्ता: इस कार्यक्रम को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने संबोधित किया।
- ◆ उद्देश्य: इस कार्यक्रम का लक्ष्य है—
 - जनजातीय चिकित्सक को सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान और जनजातीय स्वास्थ्य सुधार में सहयोगी भागीदार के रूप में पहचानना तथा शामिल करना।
 - भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग-थलग जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच तथा प्रभावशीलता को मज़बूत बनाना।
 - जनजातीय क्षेत्रों में संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, तपेदिक और कुष्ठ रोग को समाप्त करना।
- ◆ राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला: भारत के पहले भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला (B-THO) की स्थापना के लिये ICMR-क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, भुवनेश्वर के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए। यह पहल प्रोजेक्ट DRISTI के अंतर्गत जनजाति-विशिष्ट स्वास्थ्य डेटा और अनुसंधान के लिये की गई है।
- ◆ प्रोजेक्ट DRISTI: यह केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और ICMR के सहयोग से एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य जनजाति-विशिष्ट स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तैयार करना है।
 - इसका लक्ष्य जनजातीय आबादी के लिये स्वास्थ्य देखभाल योजना, रोग निगरानी और नीति निर्माण में सुधार करना है।
- ◆ भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला (B-THO): प्रोजेक्ट DRISTI के अंतर्गत स्थापित, यह अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य वेधशाला है।
 - जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य डेटा को एकत्रित करना, विश्लेषण करना और साझा करना, स्वास्थ्य प्रणाली में जनजातीय चिकित्सकों को शामिल करना तथा जनजातीय क्षेत्रों में रोग रोकथाम एवं अनुसंधान का समर्थन करना।

MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में टेक्नोलॉजी सेंटर को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों ?

जनवरी 2026 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) ने हिमाचल प्रदेश में दो नए MSME टेक्नोलॉजी सेंटरों की स्थापना को स्वीकृति दी।

मुख्य बिंदु

- ◆ स्थान: ये केंद्र ऊना ज़िले के पंडोगा औद्योगिक क्षेत्र और सोलन ज़िले के परवाणू औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किये जाएंगे।
- ◆ वित्तपोषण: प्रत्येक केंद्र की अनुमानित निर्माण लागत लगभग ₹10 करोड़ (₹100 मिलियन) है।
- ◆ राष्ट्रीय संदर्भ: ये दो केंद्र भारत में 13 नए प्रौद्योगिकी/एक्सटेंशन केंद्रों की स्थापना की व्यापक योजना का हिस्सा हैं।
- ◆ अवसंरचना: पंडोगा सुविधा को हारोली विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा कम्युनिटी सेंटर भवन में स्थित किया जाएगा, ताकि संचालन में तेजी लाई जा सके।
- ◆ उद्देश्य: ये केंद्र वर्तमान और नई औद्योगिक इकाइयों को उन्नत तकनीकी सहायता, नवाचार समर्थन तथा आधुनिक मशीनरी प्रदान करेंगे।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ कौशल विकास: प्राथमिक फोकस युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना है, विशेषकर उच्च तकनीकी क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स में, जिनमें कुछ कार्यक्रम वर्चुअल मोड में भी उपलब्ध होंगे।
- ❖ औद्योगिक वृद्धि: इस पहल का उद्देश्य इंजीनियरिंग, प्लास्टिक और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना तथा राज्य में नए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।
- ❖ महत्त्व: ये नई सुविधाएँ बड़ी में मौजूदा MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की पूरक होंगी, जो पहले ही क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण और उत्पादन सहायता प्रदान कर रहा है।

त्रिपुरा में 48वाँ कोकबोरोक दिवस समारोह

चर्चा में क्यों ?

त्रिपुरा ने 48वाँ कोकबोरोक दिवस (जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है) को राज्य-व्यापी सांस्कृतिक उत्साह और नई भाषायी मांगों के साथ मनाया। यह दिवस 19 जनवरी, 1979 को तत्कालीन राज्य सरकार के तहत कोकबोरोक को त्रिपुरा की आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में मान्यता मिलने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु

- ❖ आधिकारिक समारोह: मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने नई दिल्ली स्थित त्रिपुरा भवन में समारोहों का नेतृत्व किया, जहाँ उन्होंने कोकबोरोक को राज्य की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने वाली एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बताया और इसके संवर्द्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
- ❖ सांस्कृतिक रैलियाँ: पूरे राज्य में प्रमुख रैलियों का आयोजन किया गया, जिनमें अगरतला में लगभग 3,000 प्रतिभागियों की सहभागिता के साथ एक भव्य जुलूस भी शामिल था।
- ❖ सरकारी पहल: भाषायी विरासत के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर कोकबोरोक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की।
 - ⦿ सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिये जनजातीय और गैर-जनजातीय समुदायों के एकीकरण के प्रयास किये।
- ❖ स्मरण: यह दिवस 19 जनवरी, 1979 की स्मृति में मनाया जाता है, जब कोकबोरोक को पहली बार बंगाली और अंग्रेज़ी के साथ आधिकारिक राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था।
- ❖ भाषा: कोकबोरोक तिब्बती-बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है और बोरोक (त्रिपुरी) समुदाय की मातृभाषा है।
 - ⦿ हालाँकि 1979 में मान्यता मिलने के बावजूद, इसे अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जिससे इसे राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण सीमित है।
- ❖ क्षेत्र: कोकबोरोक मुख्य रूप से त्रिपुरा के स्वदेशी त्रिपुरी समुदायों द्वारा बोली जाती है और पड़ोसी बांग्लादेश में भी प्रचलित है।

IIT दिल्ली में पावर सेक्टर रेगुलेशन के लिये CoE

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने IIT दिल्ली में पावर सेक्टर रेगुलेशन के लिये उत्कृष्टता केंद्र (CoE) का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- ❖ सहयोगी संस्थान: यह उत्कृष्टता केंद्र (CoE) IIT दिल्ली, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड इंडिया) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मैन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **उद्देश्य:** यह विद्युत क्षेत्र के विनियमन में नियामक अनुसंधान, परामर्श सहायता, क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:** यह CoE विद्युत क्षेत्र के विनियमन, बाज़ार संरचना, ग्रिड संचालन, ऊर्जा संक्रमण, डीकार्बोनाइजेशन मार्गों, डिजिटलीकरण, ऊर्जा भंडारण तथा ग्रीन हाइड्रोजन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर बहु-विषयक अनुसंधान करेगा।
- **क्षमता निर्माण:** यह संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने में सहायता करेगा और नियामकों, नीति निर्माताओं तथा अन्य पेशेवरों के लिये संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा।
- ◆ **ऊर्जा संक्रमण में भूमिका:** विश्लेषणात्मक उपकरणों एवं साक्ष्य-आधारित अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करके यह केंद्र स्वच्छ ऊर्जा, प्रतिस्पर्धी बाज़ारों और उपभोक्ता-केंद्रित सुधारों की दिशा में भारत के संक्रमण को समर्थन प्रदान करेगा।
- ◆ **संस्थागत मॉडल:** यह साझेदारी नियामक नेतृत्व (CERC), प्रणाली संचालन (ग्रिड इंडिया) और शैक्षणिक उत्कृष्टता (IIT दिल्ली) को एकीकृत करती है, ताकि भविष्य-उन्मुख नियामक ढाँचों के निर्माण में मार्गदर्शन मिल सके।

महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट से एक दुर्लभ सीसिलियन की खोज

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट से ब्लाइंड सीसिलियन की एक नई प्रजाति की खोज की घोषणा की है, जिसका नाम गेगेनोफिस वाल्मीकि (*Gegeneophis valmiki*) रखा गया है। यह खोज इस वंश (जीनस) के लिये एक दशक से अधिक समय बाद पहली खोज है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **स्थान:** इस प्रजाति को पहली बार वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित वाल्मीकि पठार से एकत्रित किया गया था।
- ◆ **व्युत्पत्ति (Etymology):** इसका नाम खोज स्थल के निकट स्थित ऐतिहासिक महर्षि वाल्मीकि मंदिर के नाम पर रखा गया है, जो प्रजातियों के नामकरण को भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की परंपरा को दर्शाता है।
- ◆ **अनुसंधान दल:** इस खोज का नेतृत्व भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने किया, जिसमें सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, बालासाहेब देसाई कॉलेज तथा म्हादेई रिसर्च सेंटर के शोधकर्ता शामिल थे।
- ◆ **आकृति:** अन्य सीसिलियन प्रजातियों की तरह गेगेनोफिस वाल्मीकि भी बिना अंगों वाले, केंचुए के समान दिखने वाला उभयचर है।
- ◆ **भूमिगत स्वभाव:** यह एक भूमिगत (भूमि के भीतर रहने वाला) जीव है, जिसकी आँखें हड्डी के नीचे छिपी रहती हैं, इसी कारण इसे सामान्यतः 'ब्लाइंड सीसिलियन' कहा जाता है।
- ◆ **पारिस्थितिक भूमिका:** ये जीव कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिये लाभकारी हैं, क्योंकि इनकी सुरंग बनाने की गतिविधि मृदा में वायुसंचार बढ़ाती है और उसकी संरचना को सुदृढ़ बनाती है, साथ ही ये मृदा में पाए जाने वाले अकशेरुकी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
- ◆ **महत्त्व: पश्चिमी घाट,** जो एक वैश्विक जैव-विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है, अनेक स्थानिक उभयचर प्रजातियों का आश्रय स्थल है।
 - वैश्विक स्तर पर लगभग 41% उभयचर प्रजातियाँ विलुप्ति के खतरे में हैं, ऐसे में नई प्रजातियों की पहचान संरक्षण प्रयासों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



C-DOT को सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिये SKOCH अवार्ड 2025 मिला

चर्चा में क्यों ?

दूरसंचार विकास केंद्र (C-DOT) को उसकी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिये 104वें SKOCH शिखर सम्मेलन में SKOCH पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान सार्वजनिक सुरक्षा, आपदा संचार और डिजिटल शासन में इसके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **SKOCH पुरस्कार 2025:** यह पुरस्कार 19 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 104वें SKOCH शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया।
- ❖ **थीम:** शिखर सम्मेलन की थीम 'रिसोर्सिंग विकसित भारत' थी, जिसमें शासन, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया गया।
- ❖ **सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन:** C-DOT का CBS एक एकीकृत, राष्ट्रीय आपदा एवं आपातकालीन चेतावनी मंच है, जिसमें कई उन्नत क्षमताएँ शामिल हैं—
 - ⦿ **भौगोलिक-लक्षित अलर्ट:** उच्च जोखिम वाले विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में मोबाइल फोनों तक जीवनरक्षक सूचनाएँ पहुँचाता है।
 - ⦿ **रीयल-टाइम बहुभाषी समर्थन:** 21 भारतीय भाषाओं में चेतावनियों का प्रसार करता है, जिससे विविध जनसमूहों तक समावेशी पहुँच सुनिश्चित होती है।
 - ⦿ **नेटवर्क अनुकूलन:** सामान्य SMS के विपरीत, सेल ब्रॉडकास्ट संदेश नेटवर्क कंजेशन की स्थिति में भी लक्षित क्षेत्र के सभी उपकरणों तक तुरंत पहुँच जाते हैं।
- ❖ **रणनीतिक महत्त्व:** यह समाधान संयुक्त राष्ट्र की 'अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल' पहल और ITU के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।
 - ⦿ यह 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियों के साथ संगत है, जिससे भारत में विभिन्न मोबाइल नेटवर्क पीढ़ियों में व्यापक कवरेज सुनिश्चित होती है।
- ❖ **आत्मनिर्भर भारत से संरक्षण:** यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और नागरिक-केंद्रित शासन को सुदृढ़ करता है तथा डिजिटल इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत पहलों के अनुरूप है।

खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 लद्दाख में

चर्चा में क्यों ?

खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG) 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में किया गया।

मुख्य बिंदु

- ❖ **उद्घाटन:** इस आयोजन का उद्घाटन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता द्वारा नवांग दोरजे स्टोबदान (NDS) स्टेडियम में किया गया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ आयोजन प्राधिकरण: यह आयोजन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है।
- ◆ खेल विधाएँ: खेलों में बर्फ पर खेले जाने वाले खेल जैसे आइस हॉकी और आइस स्केटिंग शामिल हैं।
 - इसके साथ ही फिगर स्केटिंग को पहली बार कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
- ◆ प्रारूप: 2026 संस्करण को दो चरणों में आयोजित किया गया है—
 - लेह में आइस स्पोर्ट्स
 - गुलमर्ग (जम्मू एवं कश्मीर) में स्नो इवेंट्स
- ◆ लद्दाख की खेल नीति: केंद्र शासित प्रदेश की पहली खेल नीति का उद्देश्य प्रतिभा की पहचान, समावेशी खेलों को बढ़ावा, महिलाओं और दिव्यांग खिलाड़ियों को समर्थन, छात्रवृत्तियाँ, नौकरी में आरक्षण तथा विश्व-स्तरीय खेल अवसरचना का विकास करना है।
- ◆ महत्त्व: इन खेलों का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्रदान करना, घरेलू प्रतियोगिताओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना तथा हिमालयी क्षेत्र में विंटर गेम्स की अवसरचना का विकास करना है।

नई दिल्ली में द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

बौद्ध दर्शन के वैश्विक प्रसार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जनवरी 2026 में नई दिल्ली में द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

- ◆ स्थल: भारत मंडपम, नई दिल्ली।
- ◆ आयोजक: यह शिखर सम्मेलन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- ◆ विषय: 'Collective Wisdom, United Voice, Shared Coexistence' अर्थात् सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज़, पारस्परिक सहअस्तित्व।
- ◆ उद्देश्य: करुणा, ज्ञान, सद्भाव जैसे शाश्वत बौद्ध मूल्यों को उजागर करना और सामाजिक शांति, नैतिक नेतृत्व, पर्यावरण और कल्याण के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करना।
- ◆ चर्चा के प्रमुख क्षेत्र: सामाजिक सद्भाव, उद्यमिता एवं सम्यक आजीविका, स्वास्थ्य सेवा एवं सतत जीवन, बौद्ध शिक्षा और संघ की परंपराएँ।
- ◆ प्रदर्शनियाँ: पवित्र अवशेष, सांस्कृतिक जुड़ाव तथा विरासत से विश्व थीम के अंतर्गत भारत में बुद्ध धम्म के प्रचार-प्रसार का समग्र प्रस्तुतीकरण।
- ◆ AI पहल: बौद्ध ज्ञान के प्रचार और अधिगम में सहायता के लिये 'कल्याण मित्र' के रूप में अपनाए गए एआई-आधारित बौद्ध भाषा मॉडल, नोरबू का परिचय।
- ◆ महत्त्व: यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संवाद, सांस्कृतिक कूटनीति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका को और सशक्त करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



स्ट्राइप्ड टाइगर चंडीगढ़ की राजकीय तितली घोषित

चर्चा में क्यों ?

चंडीगढ़ के राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) ने स्ट्राइप्ड टाइगर को आधिकारिक रूप से केंद्रशासित प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया है, जो जैव विविधता की मान्यता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्य बिंदु

- ♦ **चयन प्रक्रिया:** वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा शहर की प्राकृतिक विरासत के लिये उपयुक्त प्रतीक चिह्न निर्धारित करने हेतु एक वर्ष तक चलने वाला चयन अभियान संचालित किया गया।
 - स्ट्राइप्ड टाइगर का चयन ऑनलाइन सार्वजनिक मतदान के माध्यम से हुआ, जिसमें इसे कुल वोटों का लगभग 54% प्राप्त हुआ।
 - इसने तीन अन्य चयनित प्रजातियों – ब्लू टाइगर, प्लेन टाइगर और जेज़बेल (Jezebel)
 - को पीछे छोड़ दिया।
- ♦ **चयन का आधार:** अपनी आकर्षक उपस्थिति और अनुकूलनशीलता के कारण इसे चुना गया है तथा यह सुखना वन्यजीव अभयारण्य और सेक्टर 26 तितली पार्क सहित पूरे केंद्रशासित प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
- ♦ **स्ट्राइप्ड टाइगर तितली के मुख्य तथ्य:**
 - **रूप-रंग:** इस तितली के पंख चमकीले भूरे-नारंगी रंग के होते हैं जिन पर गहरी काली धारियाँ होती हैं, जो इसे बाघ-सदृश आकृति प्रदान करती हैं।
 - **रक्षा तंत्र:** यह शिकारियों के लिये अरुचिकर (बेस्वाद) माना जाता है, यह विशेषता अमेरिकी मोनार्क तितली के समान है।
 - **स्थिति:** यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध है।
- ♦ **संरक्षण जागरूकता:** इस घोषणा का उद्देश्य नागरिकों और विद्यार्थियों में जैव विविधता संरक्षण तथा पर्यावरणीय चेतना को प्रोत्साहित करना है।
- ♦ **नया वन्यजीव शिक्षण केंद्र:** घोषणा के साथ ही, प्रशासक ने स्थानीय वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये एक नए वन्यजीव शिक्षण केंद्र (जैसे कि एक जैविक पार्क या बाड़ा) की स्थापना का निर्देश दिया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राष्ट्रीय वन प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की

चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL) की 88वीं बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य बिंदु

- ♦ **स्वीकृत प्रस्ताव:** समिति में संरक्षित क्षेत्रों, टाइगर रिज़र्व और इको-सेंसिटिव ज़ोन के भीतर और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित 70 प्रस्तावों पर विचार किया गया।
- ♦ **रणनीतिक अवसंरचना:** राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़कों और अवसंरचना से संबंधित 17 रक्षा संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से मुख्य रूप से लद्दाख और सिक्किम में थे।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ सार्वजनिक उपयोगिताएँ: चर्चा की गई परियोजनाओं में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, 4G टावरों के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी, सड़क उन्नयन और पारिषण लाइनों से संबंधित परियोजनाएँ शामिल थीं।
- ❖ जल सुरक्षा: मध्य प्रदेश में एक मध्यम सिंचाई परियोजना पर विचार किया गया, जिसका उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध कराकर बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ पहुँचाना और साथ ही घड़ियालों सहित वन्यजीवों के लिये जल स्थितियों में सुधार करना था।
- ❖ प्रशासनिक एवं प्रक्रिया सुधार: समिति ने पूर्व निर्णयों पर की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की तथा परिवेश पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया।
- ❖ निरंतर निगरानी: आगामी बैठकों में अनुपालन और निगरानी से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी, ताकि प्रभावी वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

SC-NBWL क्या है ?

- ❖ स्थापना: इसकी स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत की गई है।
- ❖ नेतृत्व: जहाँ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की पूर्ण अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, वहीं इसकी स्थायी समिति (Standing Committee) की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री करते हैं।
- ❖ कार्य: यह संरक्षण से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान करने वाला निकाय है तथा संरक्षित क्षेत्रों के भीतर या आसपास प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा करता है।

DGCA ने ATPL के लिये इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस सर्विस शुरू की

चर्चा में क्यों ?

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने जनवरी 2026 में एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL) के लिये इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस (EPL) सेवाएँ शुरू की हैं।

मुख्य बिंदु

- ❖ डिजिटल लाइसेंस: इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस (EPL) एक सुरक्षित डिजिटल लाइसेंस है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के अनुरूप सुरक्षा विशेषताएँ शामिल हैं।
 - ⦿ इसका उद्देश्य पायलट लाइसेंसों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, छेड़छाड़-रोधक व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा वास्तविक-समय ऑनलाइन सत्यापन को सक्षम बनाना है।
- ❖ एक्सेस प्लेटफॉर्म: पायलट एवं अन्य हितधारक इस लाइसेंस को इलेक्ट्रॉनिक DGCA (eGCA) मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से देख और प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे सुविधा तथा पारदर्शिता बढ़ती है।
- ❖ पूर्व रोल-आउट: DGCA ने इससे पहले फरवरी 2025 में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (CPL) और फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) लाइसेंस (FRTOL) के लिये EPL सेवाएँ शुरू की थीं।
- ❖ नियामक प्रभाव: यह पहल सुरक्षित, आधुनिक और भविष्य-उन्मुख डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से भारत के नागरिक उड्डयन नियामक ढाँचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- ❖ प्रासंगिकता: EPL पहल 'डिजिटल इंडिया' और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' के लक्ष्यों के अनुरूप है, क्योंकि इससे भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता घटती है तथा विमानन क्षेत्र में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



अमेलिया वाल्वरडे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का हेड कोच नियुक्त किया

चर्चा में क्यों ?

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने आधिकारिक तौर पर अमेलिया वाल्वरडे को भारतीय वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की मुख्य कोच नियुक्त किया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ अमेलिया वाल्वरडे की प्रोफाइल: कोस्टा रिका की अत्यंत अनुभवी कोच अमेलिया वाल्वरडे वर्ष 2015 से 2023 तक कोस्टा रिका महिला राष्ट्रीय टीम की मुख्य कोच रहीं और अपने लंबे कार्यकाल के लिये जानी जाती हैं।
- ◆ ऐतिहासिक उपलब्धियाँ: उन्होंने वर्ष 2015 और वर्ष 2023 के फीफा महिला विश्व कप के लिये कोस्टा रिका की टीम को सफलतापूर्वक क्वालिफाई कराया।
- ◆ विज्ञान 2047 से सामंजस्य: यह नियुक्ति AIFF की 'विज्ञान 2047' रोडमैप के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को एशिया में एक प्रमुख फुटबॉल शक्ति बनाना और भविष्य में फीफा विश्व कप के लिये क्वालिफाई करना है।
- ◆ अवसरचना पर ध्यान: कोचिंग के साथ-साथ वाल्वरडे से महिला फुटबॉल के संरचनात्मक विकास में योगदान देने की अपेक्षा है, जिसमें इंडियन विमेन्स लीग (IWL) भी शामिल है।
- ◆ वैश्विक पहचान: विश्व कप का अनुभव रखने वाली कोच की नियुक्ति भारत की AFC (एशियन फुटबॉल परिषद) क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी शक्ति बनने की मंशा को प्रदर्शित करती है।
- ◆ भारत में खेल प्रशासन: राष्ट्रीय महासंघों (AIFF) की भूमिका विदेशी विशेषज्ञता का उपयोग कर स्वदेशी प्रतिभा-भंडार विकसित करना और सतत खेल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना।

महत्वपूर्ण खनिजों के लिये भारत की पहली टेलिंग्स नीति

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने देश की पहली टेलिंग्स नीति (Tailings Policy) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य खनन अपशिष्ट जैसे टेलिंग्स, माइन डंप, स्लैग और ओवरबर्डन से महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनिजों की पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाना है।

मुख्य बिंदु

- ◆ टेलिंग्स की परिभाषा: टेलिंग्स वे अवशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ होते हैं (चट्टानों का महीन अवशेष, जल और रसायन) जो अयस्क से मूल्यवान खनिज निकालने के बाद बच जाते हैं।
- ◆ द्वितीयक स्रोतों से पुनर्प्राप्ति: यह नीति मौजूदा माइन डंप, स्लैग, फ्लाइ एश और टेलिंग्स तालाबों से 'सह-खनिजों' के निष्कर्षण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- ◆ अंतर-मंत्रालयी समन्वय: चूँकि महत्वपूर्ण खनिज विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सँभाले जाने वाले पदार्थों में पाए जाते हैं, इसलिये नीति कोयला, खान, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा मंत्रालयों के बीच समन्वित दृष्टिकोण को अनिवार्य बनाती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ तकनीकी क्रियान्वयन: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), भारतीय खान ब्यूरो (IBM) और परमाणु खनिज निदेशालय (AMD) जैसी एजेंसियाँ इन द्वितीयक संसाधनों की पहचान, नमूनाकरण तथा आर्थिक मूल्यांकन का नेतृत्व करेंगी।
- ❖ परिपत्र अर्थव्यवस्था: अपशिष्ट के पुनःप्रसंस्करण के माध्यम से यह नीति परिपत्र खनन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, नए खानों की आवश्यकता को कम करती है और भूमि क्षरण तथा जल प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय खतरों को न्यूनतम करती है।
- ❖ आयात निर्भरता में कमी: भारत लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) जैसे खनिजों के लिये भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है। टेलिंग्स के पुनःप्रसंस्करण से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और स्वच्छ ऊर्जा के लिये घरेलू आपूर्ति शृंखलाएँ सुदृढ़ होंगी।
- ❖ आर्थिक मूल्य: सह-धातुओं की पुनर्प्राप्ति (जैसे तांबे की टेलिंग्स से सेलेनियम और कोबाल्ट या जिंक अपशिष्ट से इंडियम) अरबों डॉलर के 'हिडन' खनिज मूल्य को उजागर कर सकते हैं।
- ❖ राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूपता: यह नीति राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देती है, जिससे दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

टाटा ग्रुप बना भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड; एप्पल पूरे विश्व में अग्रणी

चर्चा में क्यों ?

ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट के अनुसार, टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है, जबकि एप्पल विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित हुआ है।

मुख्य बिंदु

- ❖ ऐतिहासिक उपलब्धि: टाटा समूह \$30 बिलियन की सीमा पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है।
- ❖ ब्रांड मूल्य: समूह का मूल्य वर्ष-दर-वर्ष 10% बढ़कर \$31.6 बिलियन तक पहुँच गया है।
- ❖ वैश्विक स्थान: यह ग्लोबल टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय ब्रांड बना हुआ है और 60वाँ स्थान रखता है।
- ❖ सततता नेतृत्व: समूह भारत में सस्टेनेबिलिटी परसेप्शंस वैल्यू (SPV) में भी अग्रणी है, जिसका मूल्य \$4.3 बिलियन आँका गया है।
- ❖ अन्य प्रमुख भारतीय ब्रांड:
 - इन्फोसिस: भारत में दूसरा स्थान (मूल्य: \$16.3 बिलियन) और वैश्विक स्तर पर 132वाँ स्थान।
 - HDFC ग्रुप: भारत में तीसरा स्थान (मूल्य: \$14.2 बिलियन)।
 - LIC: भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड, जिसका मूल्य 36% बढ़कर \$13.3 बिलियन हो गया है।
 - ताज होटल्स: लगातार चौथे वर्ष AAA+ रेटिंग के साथ भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना रहा।
- ❖ विश्व का नंबर एक: एप्पल ने वर्ष 2025 के लिये \$574.5 बिलियन के मूल्यांकन के साथ विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा।
 - शीर्ष वैश्विक ब्रांडों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और NVIDIA जैसे प्रौद्योगिकी दिग्गजों ने भी अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी।
- ❖ महत्त्व: ब्रांड फाइनेंस की रैंकिंग वैश्विक और घरेलू स्तर पर कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उपभोक्ता धारणा तथा व्यावसायिक संस्थाओं की आर्थिक मजबूती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



NHAI और कोंकण रेलवे ने इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिये MoU पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों ?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) ने जनवरी 2026 में पूरे देश में सड़क तथा रेल अवसंरचना के एकीकृत नियोजन एवं विकास को मजबूत करने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु

- ♦ **आयोजक मंत्रालय:**
 - NHAI – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन
 - KRCL – रेल मंत्रालय के अधीन
- ♦ **कार्यान्वयन:** एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) परियोजनाओं की निगरानी करेगा, व्यवहार्यता अध्ययन करेगा और कार्यान्वयन में मार्गदर्शन देगा।
 - समझौता ज्ञापन 5 वर्षों के लिये मान्य रहेगा।
- ♦ **उद्देश्य:** जहाँ राजमार्ग और रेलवे आपस में मिलते हैं, वहाँ अवसंरचना विकास के लिये संयुक्त नियोजन, समन्वय एवं संसाधन अनुकूलन को सुविधाजनक बनाना।
- ♦ **सहयोग के क्षेत्र:**
 - सड़कों और रेलवे का एकीकृत विकास, जिसमें सुरंगें, पुल तथा लॉजिस्टिक्स हब शामिल हैं।
 - तकनीकी सहयोग: परियोजना प्रबंधन, इंजीनियरिंग डिजाइन, निर्माण विधियाँ और पर्यावरण प्रबंधन।
 - सुरक्षा और प्रशिक्षण: KRCL सुविधाओं पर NHAI कर्मचारियों के लिये ऑडिट एवं कौशल विकास।
- ♦ **रणनीतिक लाभ:**
 - कठिन भूभागों में KRCL के अनुभव और NHAI के राजमार्ग विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
 - माल और यात्री परिवहन के लिये शुरुआती तथा अंतिम चरण की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाना।
- ♦ **महत्त्व:** एकीकृत अवसंरचना नियोजन को दर्शाता है, आर्थिक विकास का समर्थन करता है और बहु-मोडल कनेक्टिविटी को मजबूत करता है।

ICAR और BISA ने ACASA-इंडिया लॉन्च किया तथा NICRA के 15 वर्ष की समीक्षा की

चर्चा में क्यों ?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया (BISA) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय जलवायु-सहिष्णु कृषि नवाचार (NICRA) की समीक्षा कार्यशाला तथा एटलस ऑफ क्लाइमेट अडैप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर (ACASA-India) के लॉन्च-कम-यूज केस कार्यशाला का उद्घाटन किया गया।

मुख्य बिंदु

- ♦ **ACASA-India (डिजिटल क्लाइमेट एटलस) का लॉन्च:** यह एक वेब-सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे स्थान-विशेष और डेटा-संचालित अनुकूलन योजना प्रदान करने के लिये डिजाइन किया गया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- **डेवलपर:** इसे ICAR नेतृत्व वाले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और विस्तार प्रणाली (NARES) ने BISA-CIMMYT के सहयोग से विकसित किया है।
- **कार्यप्रणाली:** यह उच्च रिजॉल्यूशन पर 15 फसलों और छह पशुधन प्रजातियों के लिये जलवायु जोखिम का मानचित्रण करता है तथा अनुकूलन विकल्पों की पहचान करता है।
- ◆ **NICRA का 15-वर्षीय मूल्यांकन:** वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया, NICRA भारत का प्रमुख कार्यक्रम है, जो तकनीकी प्रदर्शन और अनुसंधान के माध्यम से कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति सहिष्णु बनाने के लिये कार्य करता है।
- **कार्यान्वयन:** यह वर्तमान में 151 जलवायु-संवेदनशील जिलों में 200 से अधिक स्थानों पर सक्रिय है।
- ◆ **उपलब्धियाँ:** अब तक 11 जलवायु-सहिष्णु फसल किस्में विकसित की जा चुकी हैं और विभिन्न फसलों के कार्बन उत्सर्जन संकेत का आकलन किया गया है ताकि भविष्य के कार्बन क्रेडिट सिस्टम का समर्थन किया जा सके।
- ◆ **रणनीतिक बदलाव:** अधिकारियों ने यह दर्शाया कि NICRA अब एक 'निर्णायक चरण' में पहुँच चुका है और इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप एक रोडमैप की आवश्यकता है, जो व्यक्तिगत खेतों से आगे बढ़कर व्यापक परिदृश्य स्तर पर हस्तक्षेपों की दिशा में केंद्रित हो।
- ◆ **महत्त्व:** यह कार्यशाला कृषि में जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिये विज्ञान-प्रधान प्रतिक्रिया के महत्त्व को रेखांकित करती है, सहिष्णुता निर्माण को बढ़ावा देती है और भारत की खाद्य सुरक्षा तथा सततता के लक्ष्यों के अनुरूप है।
- यह बदलती जलवायु में किसानों की अनुकूलन रणनीतियों को सुदृढ़ करने में डिजिटल उपकरणों की भूमिका को भी उजागर करती है।

इंडिया एनर्जी वीक 2026

चर्चा में क्यों ?

इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026 का चौथा संस्करण, जो 27-30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा, गोवा में वैश्विक ऊर्जा अभिकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, उद्योग हितधारकों और निवेशकों को एक साथ लाएगा ताकि ऊर्जा सुरक्षा, सततता तथा निवेश अवसरों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

मुख्य बिंदु

- ◆ **सबसे बड़ा ऊर्जा मंच:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में आयोजित यह कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा मंचों में से एक के रूप में उभरने की संभावना रखता है।
- ◆ **थीम:** इसकी थीम "विकास को ऊर्जा देना, अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना और जीवन को समृद्ध बनाना है।"
- ◆ **प्रमुख उद्देश्य:** यह मंच तीन महत्त्वपूर्ण स्तंभों पर केंद्रित है: ऊर्जा सुरक्षा, निवेश को प्रोत्साहित करना (उत्प्रेरित करना) और व्यावहारिक डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन कम करने के) मार्ग।
- ◆ **विशिष्ट स्थान:** कई वैश्विक मंचों के विपरीत, IEW 2026 पूरे ऊर्जा क्षेत्र पर विचार-विमर्श करता है, जिसमें जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं।
- ◆ **प्रदर्शनी:** प्रदर्शनी में 11 जोन होंगे, जिनमें परमाणु ऊर्जा और सतत विमानन ईंधन पर केंद्रित नए खंड शामिल हैं।
- ◆ **नवाचार क्षेत्र:** अविन्या 2026 और हैकाथॉन चैलेंज 2026 जैसी पहलें स्टार्टअप भागीदारी तथा नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि 'मेक इन इंडिया' मंडप स्वदेशीकरण को बढ़ावा देता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ महत्त्व: यह ऊर्जा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- भारत के ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करता है।

गुजरात में स्थापित भारत की पहली निजी उपग्रह निर्माण सुविधा

चर्चा में क्यों ?

भारत ने अंतरिक्ष निर्माण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है, जब गुजरात के साणंद में देश के पहले निजी उपग्रह और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पेलोड निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी गई।

मुख्य बिंदु

- ◆ फैसिलिटी: पाल्मनारो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पेलोड फैसिलिटी, अज़िस्टा स्पेस सिस्टम्स द्वारा स्थापित भारत का पहला एकीकृत निजी उपग्रह और पेलोड निर्माण संयंत्र।
- स्थान: यह विनिर्माण इकाई गुजरात के साणंद स्थित खोराज औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है।
- ◆ MoU: इस परियोजना में गुजरात सरकार के साथ ₹500 करोड़ से अधिक के MoU शामिल हैं, जो मज़बूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को दर्शाते हैं।
- ◆ रणनीतिक क्षेत्र में प्रवेश: यह उन्नत उपग्रह निर्माण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रविष्टि को चिह्नित करता है, जिस पर पहले ISRO और सार्वजनिक उपक्रमों का वर्चस्व था।
- ◆ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: यह सुविधा पृथ्वी अवलोकन और रक्षा अनुप्रयोगों सहित वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह बाज़ार में भारत की प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाएगी।
- यह सुविधा उन्नत पेलोड का उत्पादन करेगी जो नागरिक क्षेत्रों (जैसे कृषि, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन) के लिये भी उपयोगी होंगे।
- ◆ उद्देश्य: इस संयंत्र का लक्ष्य इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पेलोड का स्वदेशीकरण करना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू अंतरिक्ष आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना है।
- अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को समर्थन देता है।

ह्यूमनॉइड रोबोट 'ASC अर्जुन'

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर 'ASC अर्जुन' नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है।

मुख्य बिंदु:

- ◆ पहली पहल: यह नवाचार-आधारित यात्री सेवा सुधार के तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क पर ह्यूमनॉइड रोबोट की पहली तैनाती है।
- ◆ स्वदेशी तकनीक: ASC अर्जुन को रेलवे सुरक्षा बल (RPF), विशाखापत्तनम द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है।
- ◆ भूमिका और कार्य: यह स्टेशन संचालन में RPF कर्मियों की सहायता करता है, विशेषकर यात्रियों की भीड़ के समय।
- सुरक्षा और निगरानी विशेषताएँ: इसमें घुसपैठ पहचान के लिये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS), AI-आधारित भीड़ निगरानी और RPF कंट्रोल रूम से रियल-टाइम कनेक्टिविटी शामिल है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- यात्री सहायता: यह रोबोट अंग्रेज़ी, हिंदी और तेलुगु में स्वचालित सार्वजनिक घोषणाएँ कर सकता है।
- ◆ स्वायत्त गश्त: ASC अर्जुन में बाधा-परिहार क्षमता के साथ अर्ध-स्वायत्त नेविगेशन है।
- जिससे 24x7 प्लेटफॉर्म गश्त और मानव संसाधन के बेहतर उपयोग में सहायता मिलती है।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली: इसमें आग और धुएँ की पहचान करने वाली प्रणालियाँ शामिल हैं, ताकि आपात स्थिति में समय पर कार्रवाई हो सके।
- ◆ इंटरैक्टिव डिज़ाइन: यह 'नमस्ते' जैसे मित्रतापूर्ण इशारों के साथ यात्रियों से संवाद करता है तथा वास्तविक समय की जानकारी और सहायता प्रदान करता है।
- ◆ महत्त्व: यह सुरक्षित, संरक्षित और अधिक यात्री-अनुकूल स्टेशनों के लिये तकनीक अपनाने पर भारतीय रेलवे के फोकस को दर्शाता है।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA) तथा व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शैलुके को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिये चयनित किया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार: भारतीय नागरिकों और संस्थानों को आपदा प्रबंधन (रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव एवं पुनर्वास) के क्षेत्र में असाधारण साहस तथा समर्पण के लिये सम्मानित करने हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है।
- ◆ घोषणा: प्रतिवर्ष 23 जनवरी (पराक्रम दिवस) को की जाती है।
- ◆ पुरस्कार राशि:
 - संस्थागत श्रेणी: प्रमाणपत्र और ₹51 लाख (यह राशि संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन गतिविधियों में उपयोग की जाएगी)।
 - व्यक्तिगत श्रेणी: प्रमाणपत्र और ₹5 लाख।
- ◆ नोडल मंत्रालय: गृह मंत्रालय (MHA)।
- ◆ संस्थागत श्रेणी: सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA) को हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में समुदाय-केंद्रित आपदा सहनशीलता विकसित करने के अग्रणी कार्यों के लिये मान्यता दी गई है।
- ◆ मुख्य उपलब्धि (आपदा मित्र): प्राधिकरण ने सभी ग्राम पंचायतों में 1,185 आपदा मित्रों (सामुदायिक स्वयंसेवकों) को प्रशिक्षित और तैनात किया है।
 - ये स्वयंसेवक उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान प्रथम प्रतिक्रिया देने वालों की भूमिका निभाते हैं।
- ◆ संचालनात्मक सफलता: SSDMA ने वर्ष 2023 की तीस्ता फ्लैश फ्लड तथा वर्ष 2016 के मंताम भूस्खलन के दौरान वास्तविक समय समन्वय के माध्यम से 2,500 से अधिक लोगों को बचाने और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में जानमाल की हानि को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ◆ व्यक्तिगत श्रेणी: लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शैलुके को वर्ष 2024 के वायनाड (केरल) भूस्खलन के दौरान उनके नेतृत्व के लिये राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- उनके निर्देशन में सेना की इंजीनियरिंग इकाई ने भारी वर्षा और अस्थिर भू-भाग के बीच चूरलमाला में रिकॉर्ड समय में 190 फीट लंबा बेली ब्रिज बनाया।
- ◆ महत्त्व: राष्ट्रीय स्तर पर यह दोहरा सम्मान प्रभावी आपदा प्रबंधन में संस्थागत तैयारी और व्यक्तिगत वीरता दोनों के महत्त्व को रेखांकित करता है।

WEF आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करेगा

चर्चा में क्यों ?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने आंध्र प्रदेश में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिये एक नए केंद्र (C4IR) की स्थापना की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- ◆ वैश्विक विस्तार: WEF फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के पाँच नए केंद्र स्थापित करेगा।
- ◆ भारतीय केंद्र: नया केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा।
 - भारतीय केंद्र, जिसे ऊर्जा और साइबर अनुकूलन केंद्र कहा जाएगा, ऊर्जा प्रणालियों तथा साइबर सुरक्षा रणनीतियों में नवाचार-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा।
- ◆ फोकस क्षेत्र: ये केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा संक्रमण और साइबर अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- ◆ साझेदारी मॉडल: प्रत्येक केंद्र सरकारों, उद्योगों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर विस्तार-योग्य नीति ढाँचे, पायलट परियोजनाएँ तथा क्षेत्र-विशेष समाधान विकसित करेगा।
- ◆ WEF 4IR नेटवर्क: नए केंद्र WEF के 4IR नेटवर्क का विस्तार करेंगे और उभरती प्रौद्योगिकियों को शासन तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सहायता करेंगे।
- ◆ रणनीतिक महत्त्व: डिजिटल और ऊर्जा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी शासन, सतत नवाचार तथा कार्यबल विकास के लिये क्षेत्रीय क्षमता को सुदृढ़ करता है।

त्रिपुरा में माताबारी पर्यटन सर्किट परियोजना

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा के दुम्बुर झील में ₹450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु

- ◆ उद्देश्य: माताबारी पर्यटन सर्किट का लक्ष्य त्रिपुरा में प्रमुख विरासत और प्राकृतिक स्थलों को जोड़ते हुए एक एकीकृत आध्यात्मिक-पर्यावरण पर्यटन गलियारा विकसित करना है।
- ◆ लागत: ₹450 करोड़ की यह परियोजना पूर्वोत्तर में पर्यटन अवसररचना के लिये बड़े पैमाने पर केंद्रीय निवेश को दर्शाती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) ₹276 करोड़ प्रदान कर रहा है।
- ◆ मुख्य स्थल: त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, चबीमुरा शैल-नक्काशी स्थल और डुम्बुर झील।
- प्रमुख सुविधाएँ: तैरते हुए घाट, पर्यावरण के अनुकूल रिसॉर्ट और पर्यटकों के लिये सुविधाएँ।
- ◆ अतिरिक्त परियोजनाएँ: विभिन्न विकास क्षेत्रों को शामिल करते हुए ₹750 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा।
- अगरवुड पहल: किसानों की आय और कृषि-वनिकी को बढ़ावा देने के लिये ₹80 करोड़ की अगरवुड मूल्य-शृंखला परियोजना।
- हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: ग्रीन गोल्ड पहल के तहत 22 इंजीनियर्ड बाँस परियोजनाओं को मंजूरी।
- ◆ रणनीतिक महत्त्व: 'एक्ट ईस्ट नीति' और विकसित पूर्वोत्तर के विज्ञान को समर्थन देते हुए त्रिपुरा को क्षेत्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता की।

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड ICC पुरुष T20 विश्व कप में शामिल

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आगामी ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में स्कॉटलैंड, बांग्लादेश की जगह लेगा।

मुख्य बिंदु

- ◆ विवाद: यह संकट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा सुरक्षा और संरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी राष्ट्रीय टीम को भारत भेजने से इनकार करने से उत्पन्न हुआ।
- ◆ सुरक्षा आकलन: ICC ने आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन कराया, जिसमें निष्कर्ष निकला कि भारत में बांग्लादेशी दल के लिये "कोई विश्वसनीय या सत्यापित सुरक्षा खतरा नहीं" है।
- ◆ प्रतिस्थापन: कई दौर की बातचीत और बांग्लादेश को भागीदारी की पुष्टि के लिये 24 घंटे की समय-सीमा देने के बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके चलते ICC ने उन्हें बदलने का निर्णय किया।
- ◆ स्कॉटलैंड की एंट्री: T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 14वें स्थान पर मौजूद स्कॉटलैंड वह सर्वोच्च रैंक वाली टीम थी, जो मूल रूप से क्वालीफाई करने से चूक गई थी।
 - ICC ने स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा है, जहाँ वे इंग्लैंड, वेस्टइंडीज़, इटली और नेपाल के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे।
- ◆ महत्त्व: यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि टूर्नामेंट की 20-टीम संरचना बिना किसी लॉजिस्टिक बाधा के बनी रहे।
 - यह ICC के उस रुख को भी उजागर करता है, जिसमें टूर्नामेंट की निष्पक्षता बनाए रखने और तय कार्यक्रमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है।

सर्बानंद सोनोवाल ने विड़िंजम बंदरगाह क्षमता विस्तार कार्यो का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित विड़िंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के क्षमता विस्तार कार्यो का उद्घाटन किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ❖ **विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह:** तिरुवनंतपुरम के निकट स्थित विज्ञान भारत का पहला गहरे जल वाला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के पास रणनीतिक रूप से स्थित है।
- ❖ **त्वरित की गई समय-सीमा:** मूल रूप से वर्ष 2045 तक पूर्ण होने वाली परियोजना के बाद के चरणों को वर्ष 2024 में किये गए एक पूरक समझौते के माध्यम से लगभग 17 वर्ष पहले ही आगे बढ़ा दिया गया। अब पूरी परियोजना दिसंबर 2028 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ❖ **भारी निवेश:** इस विस्तार में लगभग ₹16,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश शामिल है, जिससे कुल परियोजना लागत लगभग ₹30,000 करोड़ हो जाएगी।
- ❖ **अवसंरचना विस्तार:**
 - ⦿ **बर्थ विस्तार:** मौजूदा कंटेनर बर्थ को 2 किलोमीटर की निरंतर लंबाई तक बढ़ाया जाएगा, जिससे यह भारत का सबसे लंबा बर्थ बन जाएगा।
 - ⦿ **श्रुपट क्षमता:** कुल परिचालन क्षमता पाँच गुना बढ़कर प्रतिवर्ष 1 मिलियन TEUs से 5.7 मिलियन TEUs हो जाएगी।
 - ⦿ **हैंडलिंग क्षमता:** बंदरगाह को एक साथ पाँच मदर वेसल्स और 28,000 TEUs तक की क्षमता वाले भावी पीढ़ी के कंटेनर जहाजों को सँभालने के लिये सुसज्जित किया जाएगा।
- ❖ **परिचालन सफलता:** 3 दिसंबर, 2024 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने वाले चरण-I ने कुछ ही हफ्तों में 130% से अधिक क्षमता उपयोग दर्ज किया और 14.3 लाख से अधिक TEUs का संचालन किया।
- ❖ **रणनीतिक महत्त्व:** यह विस्तार मैरिटाइम विज्ञान 2030 और अमृत काल विज्ञान 2047 के तहत विश्व-स्तरीय समुद्री अवसंरचना विकसित करने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है।
 - ⦿ इसका उद्देश्य कोलंबो जैसे विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर भारत की निर्भरता को कम करना है।

CSIR-CRRI और JSW स्टील ने तमिलनाडु में स्टील स्लैग सड़कें बनाने के लिये साझेदारी की

चर्चा में क्यों ?

औद्योगिक अपशिष्ट को उपयोगी अवसंरचना में बदलने की एक ऐतिहासिक पहल के तहत केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) ने तमिलनाडु में इस्पात निर्माण के उप-उत्पाद स्टील स्लैग का उपयोग कर सड़कें बनाने के लिये JSW स्टील लिमिटेड, सलेम वर्क्स के साथ साझेदारी की है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **उद्देश्य:** इस्पात निर्माण से निकलने वाले औद्योगिक उप-उत्पादों (अपशिष्ट) को सड़क निर्माण के लिये उच्च गुणवत्ता वाले एग्रीगेट्स में परिवर्तित करना।
 - ⦿ इससे सतत, पर्यावरण-अनुकूल सड़कें बनने की उम्मीद है और पर्यावरणीय प्रभाव में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- ❖ **तकनीकी फोकस:** परियोजना में CSIR-CRRI द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त स्टील स्लैग रोड तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिसे पहले गुजरात, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।
- ❖ **वैलोरिकरण प्रक्रिया:** यह सहयोग इलेक्ट्रिक ऑप्टिमाइज़ेशन फर्नेस (EOF) और लैडल रिफाइनिंग फर्नेस (LRF) से निकलने वाले स्टील स्लैग को बिटुमिनस सड़कों के लिये प्रसंस्कृत एग्रीगेट्स में तकनीकी-आर्थिक रूप से परिवर्तित करने पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **प्रदर्शन परियोजना:** समझौते के हिस्से के रूप में, क्षेत्र के प्रदर्शन और स्थायित्व को प्रमाणित करने के लिये सलेम के पास एक प्रदर्शन सड़क खंड का निर्माण किया जाएगा।
- ❖ **संस्थागत नेतृत्व:** समझौता ज्ञापन (MoA) पर CSIR की महानिदेशक और DSIR की सचिव डॉ. एन. कलैसेल्वी की उपस्थिति में दोनों संगठनों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ हस्ताक्षर किये गए।
- ❖ **सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा:** औद्योगिक अपशिष्ट को निर्माण संसाधन के रूप में उपयोग कर भारत की संसाधन दक्षता और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है।
 - ⦿ **पर्यावरणीय लाभ:** कार्बन फुटप्रिंट तथा प्राकृतिक एग्रीगेट्स पर निर्भरता कम करने में सहायता करता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरणीय क्षरण में कमी आती है।
- ❖ **क्षेत्रीय प्रभाव:** यह तमिलनाडु में स्टील स्लैग सड़क तकनीक का पहला प्रयोग है, जो आगे चलकर अन्य भारतीय राज्यों में इसके व्यापक प्रसार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 में 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिये

चर्चा में क्यों ?

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस (2026) की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

- ❖ **पद्म विभूषण 2026:** पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिये दिया जाता है। वर्ष 2026 के प्राप्तकर्ता हैं—
 - ⦿ धर्मेन्द्र सिंह देओल (मरणोपरांत) - प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता
 - ⦿ न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के. टी. थॉमस - सार्वजनिक कार्य
 - ⦿ एन. राजम - शास्त्रीय संगीत
 - ⦿ पी. नारायणन - साहित्य और शिक्षा
 - ⦿ वी. एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत) - सार्वजनिक कार्य
- ❖ **पद्म भूषण:** उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिये 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण प्रदान किया गया—
 - ⦿ कला: सुश्री अलका यागिनिक, श्री ममूटी, श्री शतावधानी आर. गणेश और श्री पीयूष पांडे (मरणोपरांत)।
 - ⦿ सार्वजनिक कार्य: श्री शिबू सोरेन (मरणोपरांत), श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री वेल्लापल्ली नटेसन और श्री वी. के. मल्होत्रा (मरणोपरांत)।
 - ⦿ उद्योग: श्री उदय कोटक (व्यापार एवं उद्योग)।
 - ⦿ खेल: श्री विजय अमृतराज।
 - ⦿ चिकित्सा: कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी और डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु।
- ❖ **पद्म श्री:** कुल 113 प्राप्तकर्ताओं में कई प्रमुख उपलब्धियों वाले और 'अपरिचित नायकों' को सम्मानित किया गया—
 - ⦿ खेल: रोहित शर्मा (क्रिकेट), हरमनप्रीत कौर (क्रिकेट) और सविता पुणिया (हॉकी)।
 - ⦿ शिक्षा और विज्ञान: पूर्व UGC प्रमुख मामिदला जगदीश कुमार और IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटी।
 - ⦿ अपरिचित नायक: अंके गौड़ा (जिन्होंने 20 लाख पुस्तकों वाला पुस्तकालय बनाया) और आर्मिंडा फर्नांडीज (एशिया का पहला ह्यूमन मिलक बैंक संस्थापक)।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ विविधता: 2026 की पद्म सूची में शामिल हैं—
 - ⦿ 19 महिला पुरस्कारार्थी
 - ⦿ 16 मरणोपरांत सम्मान
 - ⦿ 6 विदेशी/NRI/PIO/OCI प्राप्तकर्ता
- ❖ महत्त्व: ये पुरस्कार भारत द्वारा समाज, संस्कृति, विज्ञान, खेल और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा स्थानीय स्तर के 'अपरिचित नायकों' के योगदान को मान्यता देने को रेखांकित करते हैं।

DRI द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट

चर्चा में क्यों ?

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में 'ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट' नामक एक बड़ा अभियान चलाया।

मुख्य बिंदु

- ❖ अभियान: सह्याद्री के दुर्गम वन क्षेत्र में गुप्त रूप से संचालित मादक पदार्थ उत्पादन नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिये DRI ने यह अभियान शुरू किया।
- ❖ स्थान: सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित मेथामफेटामाइन (मेफेट्रोन) की एक गुप्त मोबाइल लैब, जिसे पोल्ट्री फार्म (मुर्गी पालन केंद्र) की आड़ में छुपाया गया था।
- ❖ बरामदगी: 21.912 किलोग्राम मेफेट्रोन और 71.5 किलोग्राम कच्चा माल, जिससे लगभग 15 किलोग्राम मादक पदार्थ तैयार किये जा सकते थे।
 - ⦿ बाज़ार मूल्य: अवैध मादक पदार्थों का अनुमानित मूल्य ₹55 करोड़ है।
- ❖ रणनीति: यह खुफिया-आधारित निगरानी और देर रात की कार्रवाई का संयोजन है।
- ❖ राष्ट्रीय सुरक्षा: संगठित मादक पदार्थ तस्करी को रोकना, जनस्वास्थ्य की रक्षा करना और आपराधिक नेटवर्क को बाधित करना।
 - ⦿ यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में DRI की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

विंग्स इंडिया 2026

चर्चा में क्यों ?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम 'विंग्स इंडिया 2026' जनवरी 2026 में हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित होगा।

मुख्य बिंदु

- ❖ थीम: इसका थीम है—“भारतीय विमानन: भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना - डिज़ाइन से तैनाती तक, विनिर्माण से रखरखाव तक, समावेशिता से नवाचार तक और सुरक्षा से स्थिरता तक।”
- ❖ कार्यक्रम का स्वरूप: विंग्स इंडिया 2026 एक वैश्विक नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी और सम्मेलन है, जिसमें हवाई अड्डे, एयरलाइंस, विनिर्माण, MRO (मेंटनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) तथा लॉजिस्टिक्स सहित संपूर्ण विमानन मूल्य श्रृंखला को शामिल किया गया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ भारत के विमानन क्षेत्र की वृद्धि: यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, विमानों की संख्या में बढ़ोतरी और हवाई अड्डा अवसंरचना के विस्तार के साथ विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजारों में उभरा है।
 - विंग्स इंडिया 2026 क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देता है, जो UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- ◆ मुख्य फोकस: यह आयोजन विमान निर्माण, MRO और एयरोस्पेस घटक उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर बल देता है।
 - सत्रों में हवाई अड्डों और अवसंरचना, विमान लीजिंग, एयर कार्गो, ड्रोन, उन्नत वायु गतिशीलता, प्रशिक्षण तथा विमानन क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी।
- ◆ सततता पहल: सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF), ग्रीन एयरपोर्ट्स तथा डिजिटल और पर्यावरण-अनुकूल विमानन प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

तेलंगाना पुलिस ने घर बैठे FIR दर्ज कराने की सुविधा शुरू की

चर्चा में क्यों ?

तेलंगाना पुलिस ने नागरिकों को उनके निवास स्थान या चुने गए स्थान पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने की सुविधा देने वाली अपनी तरह की पहली नागरिक-केंद्रित पहल शुरू की है।

मुख्य बिंदु

- ◆ उद्देश्य: प्रक्रियागत देरी को कम करना, पीड़ितों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना तथा पुलिस सेवाओं को उन लोगों के लिये सुलभ बनाना जो भौतिक रूप से थाने नहीं पहुँच सकते।
- ◆ लागू मामलों का दायरा: प्रारंभ में यह पहल संज्ञेय अपराधों की कुछ निर्धारित श्रेणियों पर लागू होगी, जिनमें POC SO अधिनियम, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और तेलंगाना रैगिंग निषेध अधिनियम जैसे कानूनों के अंतर्गत आने वाले मामले शामिल हैं।
- ◆ प्रक्रिया: पुलिस अधिकारी पीड़ित के निवास स्थान, अस्पताल या अपराध स्थल पर जाकर प्रारंभिक बयान दर्ज करेंगे, अपराध स्थल को सुरक्षित करेंगे और बाद में पुलिस थाने में औपचारिक रूप से FIR दर्ज करेंगे।
 - पंजीकरण के बाद FIR की प्रति उसी स्थान पर ई-मेल, व्हाट्सएप या आवश्यकता होने पर हार्ड कॉपी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- ◆ मानक संचालन प्रक्रिया (SOP): समान क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये SOP जारी की गई है।
- ◆ नीति-संगति: यह पहल पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग, आपराधिक न्याय सुधारों तथा अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुँच की गारंटी के अनुरूप है।

शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र 2026 से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय वायु सेना (IAF) के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ◆ अशोक चक्र: यह वीरता, आत्मबलिदान या अदम्य साहस के असाधारण कार्यों के लिये दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है।
 - पुरस्कार के मानदंड: अशोक चक्र शांतिकाल के दौरान सबसे विशिष्ट वीरता या आत्म-बलिदान के लिये प्रदान किया जाता है, जो प्रतिष्ठा में परमवीर चक्र के समान है और युद्धकाल में दिया जाता है।
- ◆ सम्मानित व्यक्ति: शुभांशु शुक्ला को Axiom-4 अंतरिक्ष मिशन के दौरान नेतृत्व, साहस और अनुकरणीय आचरण के लिये सम्मानित किया गया।
 - वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने।
 - उनका यह सम्मान मानव अंतरिक्ष अभियानों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है और अंतरिक्ष सेवा को पारंपरिक वीरता के कार्यों के समान प्रतिष्ठा देता है।
- ◆ राष्ट्रीय महत्त्व: यह भारत की एयरोस्पेस उपलब्धियों, रक्षा-वीरता और वैज्ञानिक योगदान पर ध्यान को सुदृढ़ करता है, युवाओं को प्रेरित करता है तथा अग्रणी प्रयासों को मान्यता देता है।

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लॉन्च किया पहला आधार-इंटीग्रेटेड PATHIK सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

गुजरात पुलिस की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच देश की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी बन गई है, जिसने अपने PATHIK सॉफ्टवेयर के साथ आधार-आधारित सत्यापन को आधिकारिक रूप से एकीकृत किया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ इस तरह का पहला एकीकरण: अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने UIDAI के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत आधार सत्यापन को PATHIK सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया है।
 - इससे यह भारत में आधार के लिये ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटीटी (OVSE) के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली पहली कानून प्रवर्तन संस्था बन गई है।
- ◆ PATHIK सॉफ्टवेयर: PATHIK का पूर्ण रूप है - प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रैवलर एंड होटल इन्फॉर्मेटिक्स।
 - यह गुजरात पुलिस द्वारा सुरक्षा उद्देश्यों से होटलों, पीजी और होमस्टे में ठहरने वाले यात्रियों, मेहमानों तथा निवासियों को ट्रैक करने के लिये उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन है।
- ◆ उद्देश्य: इस एकीकरण का लक्ष्य आधार QR कोड स्कैन करके व्यक्तियों का त्वरित, कागज़-रहित और सहमति-आधारित सत्यापन संभव बनाना है।
 - गोपनीयता और डेटा सुरक्षा: यह प्रणाली आधार नंबर संग्रहीत नहीं करती, बल्कि सत्यापन के लिये डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जनसांख्यिकीय विवरण और फोटो का उपयोग करती है।
- ◆ व्यापक कार्यान्वयन: पूरे गुजरात में 9,000 से अधिक होटल पहले से ही PATHIK प्रणाली से जुड़े हैं, जिससे पुलिस को 50 से अधिक लापता व्यक्तियों का पता लगाने और कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिये व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता मिली है।
- ◆ सरकारी मान्यता: PATHIK परियोजना भारत सरकार द्वारा इसकी तकनीकी उपयोगिता के लिये राष्ट्रीय स्तर पर चुनी गई 11 परियोजनाओं में से एक है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोवाक जोकोविच ने 400वीं ग्रैंड स्लैम मैच जीत हासिल की

चर्चा में क्यों ?

सर्बिया के टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में यह उपलब्धि हासिल करते हुए ग्रैंड स्लैम एकल मुकाबलों में 400 जीत दर्ज करने वाले टेनिस इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए।

मुख्य बिंदु

- ❖ **अद्वितीय रिकॉर्ड:** वह टेनिस इतिहास में इस मुकाम तक पहुँचने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं, जिन्होंने रोजर फेडरर (369 जीत) और राफेल नडाल (314 जीत) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।
- ❖ **ऑस्ट्रेलियन ओपन में रिकॉर्ड:** उन्होंने तीसरे दौर में **बॉटिक वैन डे ज़ैंड्सचुल्य** को सीधे सेटों में हराकर यह उपलब्धि हासिल की, जो उनके शानदार करियर में एक और अध्याय जोड़ता है।
- ❖ **फेडरर के ऑस्ट्रेलियन ओपन रिकॉर्ड की बराबरी:** इस जीत के साथ, जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 102 मैच जीत के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली, जो टूर्नामेंट में उनकी दीर्घायु को दर्शाता है।
- ❖ **ग्रैंड स्लैम विरासत:** पहले से ही 24 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके जोकोविच ओपन युग में अपने रिकॉर्ड को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनकी असाधारण निरंतरता और प्रभुत्व को प्रदर्शित करता है।
- ❖ **टेनिस में महत्त्व:** 400 जीत का यह पड़ाव चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में लंबे समय तक उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रतीक है और उन्हें सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में स्थापित करता है।
- ❖ **सतहों पर बहुमुखी प्रतिभा:** इस जीत के साथ, वह तीनों ग्रैंड स्लैम सतहों- **हार्ड कोर्ट** (ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन), **ग्रास कोर्ट** (विंबलडन) और **क्ले कोर्ट** (फ्रेंच ओपन) पर 100 या उससे अधिक मैच जीत दर्ज करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए।

माइक्रोसॉफ्ट ने माईया 200 AI चिप्स लॉन्च किये

चर्चा में क्यों ?

माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी दूसरी पीढ़ी की AI चिप **माईया 200 (Maia 200)** लॉन्च की है, जो बड़े पैमाने पर AI कार्यभार के लिये कस्टम AI सिलिकॉन विकसित करने की कंपनी की रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **निर्माण:** TSMC की 3nm प्रक्रिया तकनीक से निर्मित, जिसमें 140 बिलियन से अधिक ट्रांजिस्टर शामिल हैं।
- ❖ **प्रदर्शन:** 4-बिट प्रिसीजन (FP4) में 10+ petaFLOPS और 8-बिट प्रिसीजन (FP8) में लगभग 5 petaFLOPS प्रदान करता है।
- ❖ **मेमोरी संरचना:** डेटा मूवमेंट की बाधाओं को कम करने के लिये 216GB HBM3e (हाई बैंडविड्थ मेमोरी) के साथ 7 TB/s बैंडविड्थ तथा 272MB ऑन-डाई SRAM से लैस है।
- ❖ **नेटवर्किंग:** स्वामित्व वाले फैब्रिक्स के बजाय मानक ईथरनेट पर आधारित दो-स्तरीय स्केल-अप डिजाइन का उपयोग करता है, जो 6,144 तक एक्सेलेरेटर वाले क्लस्टरों को समर्थन देता है।
- ❖ **वर्टिकल इंटीग्रेशन:** माइक्रोसॉफ्ट गूगल (TPU) और अमेज़न (Trainium) की तरह कस्टम हार्डवेयर डिजाइन कर रहा है, ताकि एनवीडिया पर निर्भरता घटाई जा सके और परिचालन लागत कम की जा सके।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **आर्थिक दक्षता:** यह चिप मौजूदा प्रणालियों की तुलना में प्रति-डॉलर प्रदर्शन में 30% का सुधार प्रदान करती है।
- ❖ **सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम ('ट्राइटन' लाभ):** माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI के साथ विकसित किया गया ट्राइटन कंपाइलर एनवीडिया के मालिकाना CUDA सॉफ्टवेयर के खुले-स्रोत विकल्प के रूप में जारी किया है, जिससे डेवलपर्स के लिये अपनाते की बाधाएँ कम हों।
- ❖ **रणनीतिक महत्त्व:** यह माइक्रोसॉफ्ट की तीसरे-पक्ष सिलिकॉन प्रदाताओं पर निर्भरता घटाने और AI परिचालन लागत को नियंत्रित करने की दिशा में प्रयासों को दर्शाता है।

राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार 2025-26

चर्चा में क्यों ??

पंचायती राज के केंद्रीय राज्य मंत्री एस. पी. सिंह बघेल ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा (MYGS) पुरस्कार प्रदान किये, जिनका उद्देश्य छात्रों को स्थानीय स्तर की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़कर भावी अभिकर्ताओं को तैयार करना है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **उद्देश्य:** 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत परिकल्पित त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का छात्रों को अनुभवात्मक अध्ययन प्रदान करना।
- ❖ **सहयोगी मंत्रालय:** यह समारोह पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय का संयुक्त प्रयास था।
- ❖ **भागीदारी:** 619 जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के 28,000 से अधिक छात्रों ने अनुकरणीय ग्राम सभा कार्यवाही में भाग लिया।
- ❖ **मुख्य पुरस्कार विजेता:** पुरस्कारों को दो प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया था—JNV और EMRS।
 - ⦿ JNV ऊना, हिमाचल प्रदेश: JNV श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया और विकास गतिविधियों के लिये ₹1 करोड़ का चेक मिला।
 - ⦿ EMRS कोसंबुडा, छत्तीसगढ़: EMRS श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया और इसे भी ₹1 करोड़ मिले।
 - ⦿ उपविजेता: दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यालयों को क्रमशः ₹75 लाख और ₹50 लाख प्रदान किये गए।
- ❖ **प्रलेखन:** MYGS पहल की प्रगति और उसके प्रभाव को संकलित करते हुए एक विस्तृत दस्तावेज जारी किया गया
- ❖ **महत्त्व:** यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत अनुभवात्मक शिक्षण को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने के प्रयासों के अनुरूप है।
 - ⦿ स्थानीय लोकतंत्र: युवाओं की भागीदारी के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के आधार को सुदृढ़ करना।
- ❖ **नागरिक शिक्षा:** 'लोकतंत्र की पाठशाला' के माध्यम से औपचारिक विद्यालय पाठ्यक्रम में लोकतांत्रिक मूल्यों को एकीकृत करना।

केरल में PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्ट्रीट वैंडर्स के लिये PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ❖ **PM SVANidhi योजना:** प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना जून 2020 में शुरू की गई एक सूक्ष्म-ऋण (माइक्रो-क्रेडिट) योजना है, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को बिना जमानत ऋण प्रदान करना और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
- ❖ **उद्देश्य:** यह क्रेडिट कार्ड स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती कार्यशील पूंजी तक त्वरित पहुँच देने के लिये बनाया गया है।
 - ⦿ इससे उन्हें अपने **व्यवसायिक खर्च** पूरा करने में सहायता मिलती है, अनौपचारिक उधारदाताओं पर निर्भरता कम होती है और एक औपचारिक क्रेडिट इतिहास बनता है।
- ❖ **वित्तीय विशेषताएँ:** PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड UPI-से जुड़ा होने की संभावना है और इसमें **रिवॉल्विंग क्रेडिट** सुविधा मिल सकती है।
 - ⦿ प्रायः यह ब्याज-मुक्त या रियायती शर्तों पर उपलब्ध होता है, जिससे निर्धारित सीमा तक कार्यशील पूंजी आसानी से मिल सके।
- ❖ **लक्षित लाभार्थी:** यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स, फेरीवाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, ठेले-कार्ट वाले तथा अन्य शहरी अनौपचारिक कामगारों को लक्षित करती है, ताकि उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा सके।
- ❖ **डिजिटल समावेशन:** ऋण सुविधा के साथ-साथ यह पहल डिजिटल भुगतान और वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा देती है, जिससे छोटे विक्रेताओं की औपचारिक अर्थव्यवस्था में भागीदारी मजबूत होती है।
- ❖ **व्यापक पहुँच:** लॉन्च के दौरान केरल में लगभग 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को PM SVANidhi ऋण या क्रेडिट कार्ड मिलने की सूचना दी गई और इसी तरह का कार्यान्वयन पूरे देश में जारी है।

गूगल डीपमाइंड का अल्फाजीनोम AI टूल

चर्चा में क्यों ?

गूगल डीपमाइंड ने अल्फाजीनोम नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरण लॉन्च किया है, जिसे यह अनुमान लगाने के लिये विकसित किया गया है कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन जीन नियमन को कैसे प्रभावित करते हैं और मानव रोगों में कैसे योगदान करते हैं।

मुख्य बिंदु

- ❖ **उद्देश्य:** गूगल डीपमाइंड द्वारा विकसित यह AI उपकरण दीर्घ DNA अनुक्रमों का विश्लेषण करने और आनुवंशिक भिन्नताओं के जैविक प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने के लिये उपयोग किया जाता है।
 - ⦿ यह मुख्य रूप से **नॉन-कोडिंग (नियामक) DNA क्षेत्रों** को लक्षित करता है, जो **मानव जीनोम का लगभग 98% हिस्सा** हैं और जीन विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ❖ **DNA विश्लेषण क्षमता:** एक साथ एक मिलियन DNA बेस पेयर्स तक का विश्लेषण करने में सक्षम, जिससे लंबी दूरी के आनुवंशिक नियामक प्रभावों का मूल्यांकन संभव होता है।
 - ⦿ **जीन अभिव्यक्ति, RNA स्लाइसिंग, क्रोमैटिन पहुँच और नियामक गतिविधि** पर उत्परिवर्तनों के प्रभाव का अनुमान लगाता है।
 - ⦿ **कैंसर, हृदय रोग, स्वप्रतिरक्षा रोग और तंत्रिका संबंधी स्थितियों** जैसे जटिल रोगों के आनुवंशिक कारणों की पहचान में सहायता करता है।
- ❖ **प्रशिक्षण डेटा:** इसे मनुष्यों तथा चूहों के बड़े पैमाने पर उपलब्ध सार्वजनिक जीनोमिक डेटासेट पर प्रशिक्षित किया गया है, ताकि DNA अनुक्रमों और जैविक परिणामों के बीच संबंध स्थापित करने वाले पैटर्न की पहचान की जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- यह एक आभासी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जो वैज्ञानिकों को महँगे और समय लेने वाले जैविक प्रयोग करने से पहले आनुवंशिक परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम बनाता है।
- ◆ उपलब्धता: वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग का समर्थन करने के लिये गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान उपयोग हेतु API के माध्यम से जारी किया गया।
- ◆ सीमाएँ: नैदानिक निदान या व्यक्तिगत चिकित्सा उपचार के लिये स्वीकृत नहीं है तथा इसकी भविष्यवाणियाँ प्रशिक्षण डेटा की गुणवत्ता और विविधता पर निर्भर करती हैं।

महाराष्ट्र की झॉंकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहला स्थान जीता

चर्चा में क्यों ?

महाराष्ट्र की राज्य झॉंकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ महाराष्ट्र झॉंकी की थीम: 'गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरता का प्रतीक' ने सांस्कृतिक विरासत, सामुदायिक भागीदारी, सामाजिक एकता और आत्मनिर्भरता पर बल दिया।
- झॉंकी में गणेशोत्सव के उत्सवों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें परंपराओं और सामुदायिक शक्ति को दर्शाया गया। नागपुर के ढोल-ताशा समूह की भागीदारी ने इसके सांस्कृतिक आकर्षण को और बढ़ाया।
- ◆ अन्य विजेता:
 - दूसरा स्थान: जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प और लोक नृत्यों के प्रदर्शन के लिये।
 - तीसरा स्थान: केरल ने वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता पर झॉंकी पेश की।
- ◆ मार्चिंग टुकड़ियाँ: तीनों सशस्त्र बलों में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट घोषित किया गया।
 - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में दिल्ली पुलिस को यह सम्मान मिला।
- ◆ मंत्रालय श्रेणी: केंद्रीय मंत्रालयों में संस्कृति मंत्रालय को अपनी प्रस्तुति 'वंदे मातरम - राष्ट्र की आत्मा की पुकार' के लिये सर्वश्रेष्ठ झॉंकी का पुरस्कार मिला।
- ◆ महत्त्व: ये पुरस्कार सांस्कृतिक प्रस्तुति में उत्कृष्टता, विषयगत रचनात्मकता को दर्शाते हैं तथा भारत की विविधता, विरासत और विकास गाथाओं को प्रदर्शित कर राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देते हैं।

PFDA ने किया NPS के लिये SAARG पर विशेषज्ञ समिति का गठन

चर्चा में क्यों ?

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की निवेश रूपरेखा की समीक्षा और आधुनिकीकरण के लिये रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम शासन (SAARG) पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

मुख्य बिंदु

- ◆ उद्देश्य: NPS के फंड प्रबंधन को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना तथा अंशधारकों के लिये दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति परिणामों को सुदृढ़ करना।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **लक्ष्य:** विविधीकरण में सुधार, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सशक्त बनाने तथा अंशधारकों के लिये उपलब्ध निवेश विकल्पों का विस्तार करके NPS की दीर्घकालिक निवेश संरचना को मजबूत करना।
- ◆ **समिति की संरचना:** SAARG समिति के अध्यक्ष **मॉर्गन स्टेनली इंडिया** के पूर्व कंट्री हेड नारायण रामचंद्रन हैं।
 - **विशेषज्ञ:** इसमें **परिसंपत्ति प्रबंधन, पूंजी बाज़ार, विनियमन और निवेश परामर्श** से जुड़े विशेषज्ञों के साथ-साथ PFRDA के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं।
- ◆ **समिति का दायित्व:** SAARG को सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिये मौजूदा NPS निवेश दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।
 - इस समीक्षा में भारत की पेंशन निवेश रूपरेखा की तुलना अग्रणी वैश्विक पेंशन प्रणालियों तथा विकसित होते घरेलू निवेश पारितंत्र से भी की जाएगी।
- ◆ **महत्त्व:** यह पहल पेंशन फंडों के **पोर्टफोलियो को अधिक सुदृढ़ बनाने, प्रतिफलों को अनुकूलित करने तथा जोखिमों को कम करने** में अहम भूमिका निभाती है।
 - यह भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत वृद्ध होती जनसंख्या के लिये वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और दीर्घकालिक घरेलू पूंजी संसाधनों को सशक्त किया जा रहा है।

केरल आधिकारिक तौर पर 'राज्य सूक्ष्मजीव' घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना

चर्चा में क्यों ?

केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर **बैसिलस सबटिलिस** को अपने **राज्य सूक्ष्मजीव (State Microbe)** के रूप में घोषित किया है और ऐसा करने वाला यह पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य प्रतीकों की सूची में किसी सूक्ष्मजीव को शामिल किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ **परिचय:** बैसिलस सबटिलिस, जिसे आमतौर पर '**हे बैसिलस (Hay Bacillus)**' कहा जाता है, एक **ग्राम-पॉजिटिव**, छड़ के आकार का बैक्टीरिया है, जो मुख्य रूप से मृदा और मनुष्यों तथा जुगाली करने वाले पशुओं के जठरांत्र संबंधी मार्ग में पाया जाता है।
 - यह जीवाणु **गैर-रोगजनक** है तथा **मृदा, किण्वित खाद्य पदार्थों और मानव आंत** में व्यापक रूप से पाया जाता है।
- ◆ **सहनशीलता:** यह कठोर, सुरक्षात्मक एंडोस्पोर बनाने की क्षमता के लिये प्रसिद्ध है, जो इसे अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे गर्मी और सूखे में जीवित रहने में सक्षम बनाती है।
- ◆ **सुरक्षा:** इसे वैश्विक खाद्य प्राधिकरणों द्वारा **GRAS (सामान्यतः सुरक्षित माने जाने वाले)** श्रेणी में रखा गया है और यह पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थों जैसे जापानी **नट्टो (Natto)** में एक प्रमुख घटक है।
- ◆ **'वन हेल्थ' को बढ़ावा:** यह कदम मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के आपसी जुड़ाव को रेखांकित करता है, क्योंकि **बी. सबटिलिस (B. subtilis)** तीनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ◆ **एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (AMR) से मुकाबला:** '**अच्छे बैक्टीरिया (गुड बैक्टीरिया)**' को उजागर करके, राज्य जनता को माइक्रोबायोम के बारे में शिक्षित करना चाहता है, जिससे एंटीबायोटिक्स के असंगत उपयोग को कम किया जा सके जो AMR का कारण बनता है।
- ◆ **जैव प्रौद्योगिकी केंद्र:** केरल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में अग्रणी बनने का लक्ष्य रखता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

